MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay. The question is:

That leave be granted to withdraw the Coal Mines (Nationalisation) Amendment Bill, 2000.

The motion was adopted.

The Bill was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up Bills for consideration and passing. The Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014.

The Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पट्टाधृति पूरा होने पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित पट्टाधृत अधिकारों को बनाए रखने के लिए रुग्ण कपड़ा-उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 और कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।

सर, मैं सदस्यों के बोलने से पहले कुछ बातें सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। सभी सदस्यों की जानकारी में है कि एन.टी.सी. एक बहुत ही प्रमुख संस्था है और आज इसकी स्थिति लगातार खराब हो रही है। विभिन्न कारणों से कई वस्त्र मिलें विगत वर्षों में रुग्ण हो गई थीं। केन्द्र सरकार ने कामगारों और जनहित में वस्त्र उद्योग के हित की रक्षा करने के मुख्य उद्देश्य से कानून के माध्यम से ऐसी मिलों को अपने कब्जे में लिया था। ऐसी 118 मिलों को दो चरणों में अर्थात 1974 में 103 और 1995 में 15 मिलों को अपने कब्जे में लिया था। इन मिलों का प्रबंधन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, एन.टी.सी. द्वारा किया जाता था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 6 अन्य मिलों को भी कब्जे में लिया गया था और इसका प्रबंधन भी एन.टी.सी. को सौंपा गया था। इन 103, 15 और 6, कुल 124 मिलों में से बाद में 5 का विलय कर दिया गया और 119 मिलों को एन.टी.सी. को हस्तांतरित कर दिया गया। केन्द्र सरकार ने जनहित में इन मिलों के प्रबंधन में पर्याप्त वित्तीय और प्रबंधकीय संसाधनों का निवेश किया। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए निवेश, बकाया ऋण और ब्याज के प्रति काफी राशि जो लगभग करीब छह हजार करोड़ रुपए आती है, वह बट्टे खाते में डाली गई थी। रुग्ण वस्त्र मिलों के प्रबंधन विशेष रूप से लीज होल्ड आधार पर मूल रूप से रुग्ण मिलों की निजी मालिकों के कब्जे वाली भूमि, जिस पर कब्जा किया गया था, के संबंध में केन्द्रीय कानूनों में कुछ कानूनी कमियों को दूर करने के लिए एन.टी.सी. अधिनियम में वर्तमान संशोधन अनिवार्य समझा गया है। इसमें शामिल मुद्दा इस तर्क से संबंधित है कि हालांकि फ्री होल्ड आधार पर रखी गई भूमि का अधिकार और हक केन्द्र सरकार के पास है और लीज होल्ड वाली भूमि को एन.टी.सी. को सौंप दिया गया था, रुग्ण वस्त्र

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

मिल का मूल स्वामी इसे लीज होल्ड आधार पर अपने पास रख रहा था और उक्त लीज होल्ड अधिकार राष्ट्रीयकरण पर केन्द्र सरकार को सौंप दिए गए थे। बाद में प्रबंधन हेतु इसे एन.टी.सी. को सौंपा गया। कतिपय मामलों में लीज की अवधि पूरी होने पर मूल पट्टेदाता मूल रूप से पट्टा आधार पर अपने पास रखी गई भूमि को सौंपे जाने के लिए न्यायालय में चले गए। एन.टी.सी. अधिनियम के मौजूदा प्रावधान के अन्तर्गत रुग्ण वस्त्र मिल की परिसम्पत्तियां अब पूर्णतया भारत सरकार के पास हैं और इसे हाथ में लिए जाने के तत्काल बाद इसका प्रबंधन एन.टी.सी. को हस्तांतरित हो जाएगा। महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा का प्रावधान केवल केन्द्र सरकार की पट्टे वाली भूमि के संबंध में है, न कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात एन.टी.सी. में किया गया है। कानूनी पहलूओं की जांच करने के पश्चात यह स्थिति स्पष्ट करने के लिए कि एन.टी.सी. अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। कानूनी आशय से समरूपता को ध्यान में रखते हुए लीज होल्ड आधार पर कब्जे वाली भूमि सहित रुग्ण वस्त्र मिलों की सम्पत्ति पूर्णतया केन्द्र सरकार के पास रहेगी। पट्टा आधार पर कब्जे वाली ऐसी भूमि केन्द्र सरकार के कब्जे में रहेगी किन्तु इसका प्रबंधन एन.टी.सी. द्वारा किया जाएगा। इस अधिनियम में एक बार संशोधन हो जाने के बाद किराया नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत पट्टे वाली भूमि के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध कानूनी सुरक्षा पट्टे वाली सम्पत्ति के लिए लागू होगी। तद्नुसार पट्टे वाली भूमि वस्त्र संबंधी कार्यकलापों के लिए उपलब्ध रहेगी। माननीय सदन को मैं बतलाना चाहूंगा कि यह सब मैंने संक्षेप में बताया। ऐसी भूमि करीब-करीब 960 एकड़ है। और जिसकी आज की बाजार में कीमत करीब दस हजार करोड़ रुपए है। थोड़ी सी कानूनी कमी के कारण जो मूल पट्टेदाता थे वे न्यायालय में जाकर यह संपत्ति अपने हक में वापस ले रहे थे, जबकि वास्तव में यह भूमि भारत सरकार और एन.टी.सी. के द्वारा संचालित हो रही है। इसलिए इस प्रकार का अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया था। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि एन.टी.सी. के बारे में लोगों की जो राय थी, उस राय को परिवर्तित करने का समय अब आ गया है, क्योंकि जो पहले तय हुआ था उसके तहत वर्तमान में जितनी मिलें कार्यरत हैं, उन मिलों में 5 मिलें जो एन.टी.सी. चला रही है, वे लाभ में चल रही हैं और इस वर्ष 2013-14 में उनका लाभ 15 करोड़ रुपए है। इसके अलावा एन.टी.सी. 11 मिलें और चला रही है और पांच मिलें ज्वायंट वैंचर में चल रही हैं, जो लाभ में चल रही हैं। सदन को मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि अभी 28/10/2014 को एन.टी.सी. बी.आई.एफ.आर. से वापस आ गई है और अब इसका नेटवर्क 1602 करोड़ रुपए का हो गया है। हम इतना कह सकते हैं कि एन.टी.सी. अब रुग्ण मिल नहीं है और हम एन.टी.सी. को सही ढंग से आगे बढ़ाकर चलाना चाहते हैं और टैक्सटाइल्स के विविधतापूर्ण कार्यों को करना चाहते हैं। इसलिए इस निवेदन के साथ कि आज देश के अंदर आवश्यकता है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं और एन.टी.सी. इसमें योगदान करेगा, सहयोग करेगा, मैं अधिक न बोलते हुए माननीय सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि इस संबंध में विचार करते हुए इस विधेयक को पारित करने में सहयोग करे। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

The question was proposed.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telengana): Mr. Deputy Chairman, Sir, being a bunkar, weaver, son of a textile worker of the erstwhile Bombay and being son of Telangana, I have very special emotion attached with this Bill.

Sir, this Bill is an improvement from the effort of Smt. Indira Gandhiji who, in 1974, evolved the National Textile Corporation by nationalizing about 120 textile mills. This Bill is an improvement of the 1995 Act. The present Government has also brought out an Ordinance and that Ordinance will be replaced by this Bill.

To begin with, if we recollect, in 1887, we had the first textile mill of the nation -- Swadeshi. It had given not only automation to the pit-loom but it has also given us the national spirit of Swadeshi. In Mumbai, Kolkata, Ahmedabad, Kanpur and in Warangal district of my Telangana, the emotions and the socio-economic linkage with the textile sector are so deep that the same have been shattered from 1982 onwards. The great Bombay textile agitation involved about 3 lakh textile workers and their 12 lakh dependent family members. In Ahmedabad, in Bilimora, in Warangal, in Sirpur of Adilabad district, if we understand the plight of mill workers who got displaced following the closure of textile mills, that itself will form into a very challenging study of socio-economic complications of the ongoing textile industry. In the recent past, the National Textiles Corporation could not deliver what Smt. Indira Gandhi had envisioned. Following the complications, as the textile mills came to a standstill with the sight of land mafia, real estate and the builders' group gradually concentrating on to the prime pieces of the land of National Textiles Corporation across Bombay, Ahmedabad, Kolkata, Kanpur and even in Warangal. The erstwhile Nizam State established the Azamzahi Mills at Warangal. It was the greatest contribution to the economy not only by Azamzahi but also by several textile mills all over the Indian Union in the times of the freedom struggle and attainment of Independence. It has not only imbibed in us the Swadeshi culture, but also enthused us towards modern technology and automation. Intermittently, the Governments of those times did not show the requisite concentration and care to protect the mills and their properties all across the nation. With this, a greater social trauma has developed. If you could understand the subsequent 1982 situation of the Great Bombay Textile Mill agitation, with so many thousands of families got into so distressful life which they could not even repair, that was still impacting the newer generations. Being a son of the textile worker of Bombay, I do have the agony-filled memories of those agitations. While we travel in Gujarat from Navasari via Ganadevi towards Bilimora, there was a wonderful textile mill employing more than 3,000 full-time workers. After the shutdown of the Bilimora Mill, the tragedy, the cry of workers was so ghastly that that has shattered even the economy of several districts of my Telangana. This was happening in Maharashtra,

[Shri Ananda Bhaskar Rapolu]

this was happening in Uttar Pradesh, this was happening in West Bengal, this was happening in Telangana besides Gujarat. This tragedy has alerted our UPA Government. In the last ten years, we were always attentive and vigilant. With that vigilance, we were trying to take the necessary protective measures and precautions. This Bill is part of that protective effort of Soniaji-led Indian National Congress-led UPA Government. We tried to evolve such holistic approach to protect the whole of the textile and its dependent industry throughout the nation. Being a son of Telangana, if I forget to mention about the tragedy of Antargaon Spinning Mill of Karimnagar district, the cotton growing farmers and the spinning industry dependent labourers will not excuse me. That was the tragedy going on. To alleviate those complications and those socio-economic complications UPA Government has worked out three-pronged efforts. First, in 2011, the then UPA Government came out with an extraordinary forward-looking RRR scheme with more than ₹ 6,000 crore fund allocation to protect the handloom weavers throughout the nation. In the last two Budgets of UPA Government, we tried to understand and focus on the complications of powerloom industry; though it looks alike, like textiles, powerloom sector is neither handloom nor textile because of its critical gaps in the technology and automation. Keeping that complication in view, we, our UPA Government tried to evolve a separate policy towards powerloom industry to protect and to cater to its energy, raw material needs and marketing needs. For that we tried to evolve a credit facility with lesser interest rate, not only to the handloom weavers but also to the powerloom sector. That was the effort went into to protect the National Textile Corporation and its components throughout the nation by our UPA Government. If you could recollect the constitution of Kamath Committee for the study and proposals of debt restructuring, we were able to give ₹ 30,000 crore relief to the textile sector. We were also trying to protect the private textile mills as well. With that effort we were able to revive, before our demitting the office in 2014 early months, 22 textile mills. This was the consistent and comprehensive effort that went into. Keeping those experiences in view, we tried to broad-base the activity, the productivity and the advancement in the technology on the platform of National Textile Corporation. At the same time, that was the effort made by us during our time to look after this spinning sector, because without protecting the spinning sector you cannot look after the needs of the textiles, in particular, in the days of global warming. We not only need to have a protective eye towards the spinning mills and their owners, but, we also need to protect the interests of cotton growers. There was certain disturbance, we were alert, four years earlier. We tried to look after the expectations and aspirations of cotton farmers. At that time, if you could kindly recollect, how was the disturbance created in Gujarat? The

then Government's leading personality, who is now the present Prime Minister of India, was almost leading that agitation. But, our UPA. Government, always wedded to the interests of workers and farmers, immediately responded to the aspirations of the cotton farmers by raising about ₹300 the minimum support price of cotton. What is happening now? If you kindly look at the present status, you will find that there are suicides across the cotton-growing fields throughout the nation. Has the present Government taken notice of it? Even after the persistent and vehement demand, the present Government is gracious enough to raise only by ₹50 the MSP of cotton. This is your concern. Before entering into the power corridors, your approach was reaching out to the poor; your slogans were giving bells like situation to the poor rural agrarian farmers and workers. They thought that the change of guard will be a change for their benefit and progress. But, now it is happening only for the rich, only for the landed people and only for the corporates. With this precaution only, when we were in the Government, this Bill had been drafted by the then UPA Government. You kindly read the various provisions provided in this Bill. It says, "The textile mills landed property must be not only of the textile mills, not only the National Textile Corporation, but it must be of Union Government. Then only the prime piece of land will be protected from the graspful-eyes of the grabbing-builders' group. With this protectionist approach, we tried to bring in this enactment. But, now, what is happening all across the nation? The farmers, cotton farmers in particular, are in a lot of distress. The spinning sector is facing a big challenge. The handloom weavers are in big distress. What is happening in Varanasi, the great constituency, the present Prime Minister of India? What are they expecting of the Varanasi Saree-weaving labourers? What is happening all across the handloom sector in different States, namely, Telangana, Andhra, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam and other North-eastern States? Could we understand their problems? The handloom-weaving sector is also facing problems. In such a situation, you are yet to come out with proper remedies to the existing complications. Even your approach towards the RRR Scheme, initiated by our Union Government, championed by our leader Shrimati Sonia Gandhi, is not showing any progress to alleviate the complications of handloom weavers. The textile mill workers, in particular, if we understand the Maharashtra and Gujarat complications in power loom industry, are not at all getting the inter-State migration workers' benefits. They are not at all having the job hours. They are having arduous life. So, they have to come out of that work and are getting displaced by travelling back to their native place. This is the situation there. In such a situation, the hon. Minister is gracious enough to record that the National Textile Corporation's Protection and Expansion Programme. There is every necessity of it. Can you think of Sirpur Kaghaznagar Mill? Can you think of Azam Jahi Mills of Warangal district? Let us not forget the mills across Maharashtra, Gujarat, Kanpur and

[Shri Ananda Bhaskar Rapolu]

other cities of Uttar Pradesh; Kolkata and other cities of West Bengal. When you are having a comprehensive approach towards them, you will look at it not as a piece of land, you will look at it as a place for resource generation, a place for productivity. To enrich the corporate textile sector, there is every necessity to have the public sector undertaking perfect. For that there is every necessity to protect the National Textile Corporation. When you ensure the protection of the National Textile Corporation and its properties, only then can we expect the bedrock of the productivity of Indian industry, that is, textile. When you are able to protect through the governmental support, we can expect that we are assuring future towards not only the energy needs but also the cloth needs of the nation. For that let us not look towards the pieces of land of NTC as leasehold places. They are the places of productivity. For that there is every necessity to revive it and with several infrastructure inputs, including the captive power generation facilities of non-conventional ways. Besides that if you look towards the National Textile Corporation as a future basis for the 'make in India' which you are boasting of, it will add feather not only to you, it will also protect the weaving interest of the nation which, in turn, will save the clothing needs of the nation. With this, I support the Bill for the enactment. Thank you very much.

SHRI V.P. SINGH BADNORE (Rajasthan): Sir, I stand to support the Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014. My friend from the other side, who knows a lot about the textile industry, was right in many, many ways. I support this Bill. We had come out with an Ordinance because there were some problems regarding the ownership of the land. Now if you go into the history of the textile industry in India, there were lands, there were textile industries, which came about in major cities of the country like Bombay, Ahmedabad, Kolkata, and even in South. There were chunks of land and they had these textile industries. But over the years, the owner did not really pay heed to the renovation, refurbishment, getting new spindles. And they were leading these textile industries. That was the reason why the labour, the employees were the people who were suffering the most. They were in these big, big cities where these big chunks of land were there. That was the time and very rightly that the Government of the day had this Sick Textile Undertaking Nationalisation Act, 1974. It was later in 1985 that the Sick Industrial Companies Special Provisions Act, 1985 came about. By this the Government took over these mills from these owners. Some were under the joint venture. They tried all sorts of things to revive them. But it was felt that some became viable, some did not and the story goes on and on. Today the story is a little different. There are 119 NTC owned, regulated mills but only, as the Minister was saying, 28 of them are

still surviving under the NTC. Now these mills and the land became a problem because the people who had given this land originally, when this leasehold was over, approached the courts and said that 'these are ours.' They had given it to the owners. Thereafter, the NTC had taken that over. Hundreds and thousands of crores of rupees were spent by the NTC. At one time, the Government also said that they must revive them. And, this was through the BIFR and the Board tried to revive them. I support this Bill wholeheartedly. I commend the Minister because the new Minister is taking a lot of pains. Please see the problems of the NTC mills and why they are not functioning. I come from a city -- which is called the Manchester of Rajasthan, if not of India -- Bhilwara. There are a lot of textile mills. The BIFR is not only for the NTC, but for the private owners also. Many textile mills, not only in Ahmedabad and Bombay, but in Bhilwara also, have taken advantage of the BIFR. They have imported handloom machines, spindles, etc. There is activity of weaving and spinning. But I must tell the hon. Minister that the BIFR has not paid to many of these people who had brought in these new machines. Automation is required a lot in this industry. There was a time when it was labour-oriented. Then, the automation came. So, you have to do something about the employees. If the employees had to be spruced, then, these people need to be given the VRS. The VRS must be there. Even there is a scheme 'Modified VRS'. We have to take care of the employees and the labourers who have spent their life in it. You cannot say one day that now you go out because we cannot afford you any more because there is automation in the mill. So, that is another issue that you must look into. But as far as this Bill is concerned, it is in the right direction. Please ensure that the owners do not get hold of those very, very expensive pieces of land. There is land worth crores and crores of rupees in Kolkata, Mumbai, Ahmedabad, and in many other cities. They must get back to the Government. If the Government can run them, it is okay. But this must vest in the Government and the Government will see to it what they have to do of this land. Those lands cannot be handed over back to the people who had leased out these lands to those people who, in turn, had given it to the NTC. There are other things also which the NTC must look into. And, what can the NTC do? There is a severe competition, not only in India, but abroad also. Today, the export of textiles of India is sought in the world. We are exporting to the US; we are exporting to England; we are exporting to Africa. But how is it that the private players are doing so well and the NTC has not been able to do well? If you look into these aspects, I am sure the NTC also can come up and compete with the private players. I must say here that the cotton of India is much sought after. And, it is not just of India, but we are getting competition, now, from Pakistan and Bangladesh also. So, we have to be in competition with our neighbourhood. And, in that, what must be done; how can we be ahead of these countries? One is that the

[Shri V.P. Singh Badnore]

issue of labour must be looked into. We do not get cheap labour any more. There was a time when cheap labour was available, but now it is not. So, the competition is severe. In the export market also, it is this competition that we have to survive. The biggest competition today is from China.

Sir, NTC has 119 mills and only 28 mills are running. In China, there are hundreds and thousands of such mills which are also exporting and that too, at a cheaper rate. So, you have to see how they are surviving. You have to see what new things we can do to put India back into the competition that is there. Sir, the problem lies only in one thing and that is the purchase of the NTC. The NTC buys at a rate much higher than that of the private industries. That is why we are not able to survive this competition. If we are not competitive, it is very difficult for us to be viable. For that viability, you have to see where you can cut cost. You have to cut cost at every level. Cutting costs at every level is very important. Sir, the hon. Minister is taking so much pain, and I think that he is going in the right direction. First and foremost, this land belongs to the Government and the NTC. It cannot be taken away. This is number one.

Number two, as regards the revival of the NTC mills, presently the number is only 28: Can you make it a bigger number? How will you do it? How much money you will have to put into it to see that we survive in this very competitive world? Thank you very much.

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी के नेता आदरणीय प्रो. राम गोपाल यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है।

*[(**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया**) पीठासीन हुए।)]*

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कपड़ा इंसान के जीवन का सबसे करीबी साथी है। जब बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आंख खोलता है, तब उसका कपड़े से वास्ता होता है और जब आखिरी सांस लेता है, मरघट या कब्रिस्तान तक जाता है, तब कपड़ा ही साथ जाता है, सारे अज़ीज़दार उसका साथ छोड़ जाते हैं। अगर मैं ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो मैं सोचता हूं कि यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे नेता ने मुझे इस महान सदन में बोलने का मौका दिया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में जब टैक्सटाइल की बात चलेगी, तो वह बात विचारों से जुड़ जाएगी और बगैर गांधी के वह बात पूरी नहीं होगी। गांधी ने समाज में जो अपना पूरा दर्शन फैलाया, उसमें कपड़े का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यह बहुत अच्छा बिल है, बिल की नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन अगर बिल में कहीं कोई कमी है, तो माननीय मंत्री जी को फराख़दिल से, उस बिल में संशोधन करना चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस कर्ब के साथ अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि

हिंदुस्तान की एक बटा पांच आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार है। माननीय मंत्री जी, मैं एक रिपोर्ट के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने संसद में स्वयं स्वीकार है कि 2010 से 7 अगस्त, 2013 तक निजी क्षेत्रों की बंद मिलों के कामगारों को "वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना" के अंतर्गत आवंटित की गई निधि से उत्तर प्रदेश का एक भी कामगार लाभान्वित नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि जब-जब टैक्सटाइल की बात चलेगी, जब-जब कपड़े की बात चलेगी, तो बनारस का सिसकता हुआ साड़ी उद्योग सामने आ जाएगा। तब आपके सामने बुंदेलखंड के अन्दर मऊरानीपुर का सिसकता हुआ हैंडलूम आ जाएगा, तब आपके सामने मेरठ का बंद होता हुआ हैंडलूम सामने आ जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि जो मैंने कहा है, उस पर सरकार गौर करे।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में कपड़े के सम्बन्ध में, टेक्सटाइल के सम्बन्ध में कोई बिल आया है, तो हम समाजवादियों का इस क्षेत्र से बड़ा रिश्ता रहा है। शरद जी यहां बैठे हुए हैं, वे हम लोगों के नेता हैं। जॉर्ज फर्नांडीज साहब ने जब टेक्सटाइल का आन्दोलन चलाया था, तब हम लोग नौजवान थे, हम मुम्बई जाकर जेलों में रहे, लेकिन आज वे मिलें बंद हो गई हैं। मजदूरों के वे चेहरे भी गायब हो गए, जो समाजवादी आन्दोलन का हिस्सा थे। वे मजदूर नेता भी दुनिया से चले गए। अगर उनके बच्चे बचे रह गए हैं, तो कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। इसलिए जो भी बिल आए, जमीन जरूर वापस होनी चाहिए। हमारा यह भी फर्ज है। आप यह देखिए कि कानपुर के अन्दर लाल इमली नाम से कपड़े की एक फैक्टरी थी। माफ कीजिए, उसके अन्दर करोड़ों रुपए की सम्पत्ति थी। मजदूर सिसक रहे हैं, मजदूर रिक्शा चला रहे हैं और मिल ने गरीबों से जो कपास और रॉ मैटीरियल खरीदा था, उनको उनके पैसे नहीं दिए गए हैं और भू-माफिया ने वहां कब्जा कर लिया है, जमीन बेच दी गई है। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस जमीन को लौटना चाहिए और हमारे उत्तर प्रदेश के उन सिसकते हुए मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का बेजोड़ स्थान है। औद्योगिक उत्पादन रोजगार के अवसर पैदा करता है और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका स्थान लगभग 14 प्रतिशत है, सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान 4 प्रतिशत है और विदेशी आय में इसका योगदान 13.5 प्रतिशत है। यह अनुमानित 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसमें बड़ी संख्या में मुसलमान, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग और महिलाएं शामिल हैं। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास का भारतीय अर्थव्यवस्था से सीधा रिश्ता है। देश के वस्त्र उद्योग में कपास और मानव निर्मित धागों का अनुपात 56.44 प्रतिशत है। वर्तमान में भारत कपास पैदा करने वाला विश्व का दूसरा बड़ा देश है और यहां कपास की पैदावार 41.3 लाख टन है, जो विश्व उत्पादन का 16 प्रतिशत है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, विश्व स्तर पर भारत रेशम का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है एवं विश्व के कच्चे रेशम के उत्पादन में 18 प्रतिशत का योगदान देता है। भारत वे अद्वितीय क्षमताएं रखता है, जहां सभी प्रकार के रेशम के धागे पैदा होते हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब गांधी जी ने यह कहा कि खादी धारण करो, तो खादी के कपड़े की क्वालीटी की बात नहीं थी, बात थी समाज की उस समरसता

[चौधरी मुनव्वर सलीम]

की, उस ताने-बाने की और समाज के उस आखिरी आदमी की, जो सिसक रहा था, जिस तक आज़ादी की हवाएं आज भी नहीं पहुंच रही हैं। लेकिन, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कपड़े के उद्योग को जिसने नुकसान पहुंचाया, उसके बारे में बिल के अन्दर कोई बात नहीं की गई है। अगर बनारस का साड़ी उद्योग सिसक रहा है, तो वह इसलिए सिसक रहा है कि वहां चीन के धागे ने कब्जा कर लिया है। चीनी धागे ने बनारस की साड़ी को बरबाद कर दिया है। अभी त्यागी जी चले गए, जैसा वे कह रहे थे और प्रोफेसर साहब की हर तकरीर में यह बात कही जाती है, मैं कहना चाहता हूं कि हम स्वदेशी का नारा लगाने वाले लोग, हम स्वदेशी जागरण चलाने वाले लोग, हम स्वदेशी मान्यताओं को फैलाने वाले लोग, हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि कपड़े के क्षेत्र में इसने जो फराख़दिली दिखायी है, इसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए वह इस बिल में कहीं कोई मुकाम बनाएगी। अगर हम कपड़े का उद्योग स्वदेश पर ही आधारित रखेंगे, तो आपने देश के मजदूरों को उससे रोजगार मिलेगा, हमारे किसानों को रोजगार मिलेगा, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। खुली बाजार व्यवस्था हमारे कपड़ा उद्योग को गर्त में ले जाने का सबसे बड़ा साधन बनी हुई है। इसके बारे में बिल में एक बात भी नहीं कही गई है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ जाइए और देखिए, वहां पर चापा का जो नामवर सिल्क उद्योग था, वह सिसक रहा है। आप भागलपुर चले जाइए, वहां का सिल्क उद्योग समाप्त हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इन सब बातों को बिल में स्थान देंगे, साथ ही मेरे इस मशवरे को भी शामिल करेंगे कि अगर कपड़ा उद्योग स्वदेशी मान्यताओं पर, स्वदेशी विचारधारा पर और स्वदेशी मन पर आधारित होगा, तो इसमें इज़ाफा जरूर होगा। ऐसा करने से हमारे भारत का मान भी बढ़ेगा और भारत की आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी, चूंकि खेती के बाद इसी उद्योग का दूसरा स्थान है।

अंत में इस उम्मीद के साथ कि मेरे संशोधनों पर माननीय मंत्री जी गौर करेंगे, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। शुक्रिया।

†**چودھری منوّر سلیم (اتّر پردیش)** : مانّئے اپ سبھا ادھیکش مہودے، سلیم بڑا بسٹوریکل ہے، وہ کافی ہے۔ میں اپنی پارٹی کے نیتا آدرنئے پروفیسر رام گوپال یادو جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم مدّعے پر بولنے کا موقع دیا ہے۔

(اپ سبھا ادھیکش (ڈاکٹر ستیہ نارائن جٹیہ) صدر نشین ہوئے)

مانّئے اپ سبھا ادھیکش مہودے، کپڑا انسان کے جیون کا سب سے قریبی ساتھی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، تب اس کا کپڑے سے واسطہ ہوتا ہے اور جب آخری سانس لیتا ہے، مرگھاٹ یا قبرستان تک جاتا ہے، تب کپڑا ہی ساتھ جاتا ہے، سارے عزیز دار اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر میں ایسے اہم وشئے پر بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ میرا سوبھاگیہ ہے کہ اس مہان سدن میں میرے نیتا نے مجھے موقع دیا ہے۔

†Transliteration in Urdu Script.

مانّئے اپ سبھا ادھیکش مہودے، ہندوستان میں جب ٹیکسٹائل کی بات چلے گی، تو وہ بات وچاروں سے جڑ جائے گی اور بغیر گاندھی کے وہ بات پوری نہیں ہوگی۔ گاندھی کے سماج میں جو اپنا پورا درشن پھیلایا، اس میں کپڑے کا اہم مقام ہے۔ وہ بہت اچھا بل ہے۔ بل کی نیت بہت اچھی ہے، لیکن اگر بل میں کہیں کوئی کمی ہے، مانّئے منتری جی کو فراخ دلی سے اس بل کا سنشودھن کرنا چاہئے۔

مانّئے اپ سبھا ادھیکش مہودے، میں کرب کے ساتھ اپنی بات شروع کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی 1/5 آبادی اتر پردیش میں رہتی ہے۔ اتر پردیش میں ہماری پارٹی کی سرکار ہے۔ مانّئے منتری جی، میں ایک رپورٹ کے آدھار پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے سنسد میں خود سویکارا ہے کہ 2010 سے 7 اگست، 2013 تک نجی چھیتروں کی بند ملوں کے کام۔گاروں کو "وستر کام۔گار پنرواس ندھی یوجنا" کے انترگت آونٹت کی گئی ندھی سے اتر پردیش کا ایک بھی کام لابھانوت نہیں ہوا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ٹیکسٹائل کی بات چلے گی، جب کپڑے کی بات چلے گی، تو بنارس کا سسکتا ہوا ساڑی ادھیوگ سامنے آ جائے گا۔ تب آپ کے سامنے بندیل کھنڈ کے اندر مئورانی پور کا سسکتا ہوا ہینڈلوم آ جائے گا، تب آپ کے سامنے میرٹھ کا بند ہوتا ہوا ہینڈلوم سامنے آ جائے گا۔ اس لئے میں سوچتا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے، اس پر سرکار غور کرے۔

مانّئے اپ سبھا ادھیکش مہودے، ہندوستان میں کپڑے کے سمبندھ میں، ٹیکسٹائل کے سمبندھ میں کوئی بل آیا ہے، تو ہم سماجوادیوں کا اس چھیتر سے بڑا رشتہ رہا ہے۔ شرد جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم لوگوں کے نیتا

ہیں۔ جارج فرنانڈیز صاحب نے جب ٹیکسٹائل کا آندولن چلایا تھا، تب ہم لوگ نوجوان تھے، ہم ممبئی جاکر جیلوں میں رہے، لیکن آج وہ ملیں بند ہو گئی ہیں۔ مزدوروں کے وہ چہرے بھی غائب ہو گئے، جو سماجوادی آندولن کا حصّہ تھے۔ وہ مزدور نیتا بھی دنیا سے چلے گئے۔ اگر ان کے بچّے، بچے رہ گئے ہیں، تو کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی کچھ اور کام کر رہا ہے۔ اس لئے جو بھی بل آئے، زمین ضرور واپس ہونی چاہئے۔ ہمارا یہ بھی فرض ہے۔ آپ یہ دیکھئے کہ کانپور کے اندر 'لال املی' نام سے کپڑے کی ایک فیکٹری تھی۔ معاف کیجئے، اس کے اندر کروڑوں روپے کی سمپتّی تھی۔ مزدور سسک رہے ہیں، مزدور رکشا چلا رہے ہیں اور مل کے غریبوں سے جو کپاس اور راہ مٹیرئیل خریدا تھا، ان کو ان کے پیسے نہیں دئے گئے ہیں اور بھو-مافیا نے وہاں قبضہ کر لیا ہے، زمین بیچ دی گئی ہے۔ میں آپ کے ذریعے مانئے منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمین کو لوٹانا چاہئے اور ہمارے اتّر پردیش کے ان سسکتے ہوئے مزدوروں کو روزگار ملنا چاہئے۔

مانئے اپ سبھا ادھیکش مہودے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی ارتھ-ویوستھا میں کپڑا ادھیوگ کا بے-جوڑ استھان ہے۔ اودھیوگک اتپادن روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے اور ودیشی مدرا ارجت کرنے میں یہ چھیتر اہم رول ادا کرتا ہے۔ ورتمان میں اودھیوگک اتپادن میں اس کا استھان لگ بھگ 14 فیصد ہے، سکل اتپادن میں اس کا یوگدان 4 فیصد ہے اور ودیشی-آئے میں اس کا یوگدان 13.5 فیصد ہے۔ یہ انومانت 3.5 کروڑ لوگوں کو روزگار پردان کرتا ہے۔ اس میں بڑی تعداد میں مسلمان، انوسوچت جاتی، جن-جاتی کے لوگ اور مہیلائیں شامل ہیں۔ کپڑا ادھیوگ دیش میں کرشی کے بعد

روزگار پردان کرنے والا دوسرا بڑا چھیتر ہے۔ اس لئے اس چھیتر کی ورڈھی اور وکاس کا بھارتی ارتھ-ویوستھا سے سیدھا رشتہ ہے۔ دیش کے وستر ادھیوگ میں کپاس اور مانو نرمت دھاگوں کا انوپات 44-56 فیصد ہے۔ ورتمان میں بھارت کپاس پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا دیش ہے اور یہاں کپاس کی پیداوار 41-3 لاکھ ٹن ہے، جو دنیا کے اتپادن کا 16 فیصد ہے۔

مانئے اپ سبھا ادھیکش مہودے، وشو استر پر بھارت ریشم کا دوسرا بڑا اتپادک دیش ہے اور دنیا کے کچے ریشم کے اتپادن میں 18 فیصد کا یوگدان دیتا ہے۔ بھارت وہ بہت ساری چھمتائیں رکھتا ہے، جہاں سبھی طرح کے ریشم کے دھاگے پیدا ہوتے ہیں۔

مانئے اپ سبھا ادھیکش جی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب گاندھی جی نے یہ کہا کہ کھادی دھارن کرو، تو کھادی کے کپڑے کی کوالٹی کی بات نہیں تھی، بات تھی سماج کی اس سم-رستا کی، اس تانے بانے کی اور سماج کے اس آخری آدمی کی، جو سسک رہا تھا، جس تک آزادی کی ہوائیں آج بھی نہیں پہنچ رہی ہیں۔ لیکن اپ سبھا ادھیکش مہودے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کپڑے کے ادھیوگ کو جس نے نقصان پہنچایا، اس کے بارے میں بل کے اندر کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ اگر بنارس کا ساڑی ادھیوگ سسک رہا ہے، تو وہ اس لئے سسک رہا ہے کہ وہاں چین کے دھاگے نے قبضہ کر لیا ہے۔ چینی دھاگے نے بنارس کی ساڑی کو برباد کر دیا ہے۔ ابھی تیاگ جی چلے گئے، جیسا وہ کہہ رہے تھے اور پروفیسر صاحب کی ہر تقریر میں یہ بات کہی جاتی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سودیشی کا نعرہ لگانے والے لوگ، ہم

سودیشی جاگرن چلانے والے لوگ، ہم سودیشی مانیتاؤں کو پھیلانے والے لوگ، ہم اس سرکار سے امید کرتے ہیں کہ کپڑے کے چھیتر میں اس نے جو فراخ دلی دکھائی ہے، اس کے اوپر پابندی لگانے کے لئے وہ اس بل میں کہیں کوئی جگہ بنائے گی۔ اگر ہم کپڑے کا ادھیوگ سودیش پر ہی آدھارت رکھیں گے، تو اپنے دیش کے مزدوروں کو اس سے روزگار ملے گا، ہمارے کسانوں کو روزگار ملے گا، ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور بھارت کی آرتھک استتھی سدرڑ ہوگی۔ کھلی بازار ویوستھا ہمارے کپڑا ادھیوگ کو غرد میں لے جانے کا سب سے بڑا سادھن بنی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں بل میں ایک بات بھی نہیں کہی گئی ہے۔

مانئے اپ سبھا ادھیکش جی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھتیس گڑھ جائیے اور دیکھئے، وہاں پر چاپا کا جو نامور سلک ادھیوگ تھا، وہ مسک رہا ہے۔ آپ بھاگلپور چلے جائیے، وہاں کا سلک ادھیوگ ختم ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ منتری جی ان سب باتوں کو بل میں جگہ دیں گے، ساتھ ہی میرے اس مشورے کو بھی شامل کریں گے کہ اگر کپڑا ادھیوگ سودیشی مانیتاؤں پر، سودیشی وچار دھارا پر اور سودیشی من پر آدھارت ہوگا، تو اس میں اضافہ ضرور ہوگا۔ ایسا کرنے سے ہمارے بھارت کا مان بھی بڑھے گا اور بھارت کی آرتھک ویوستھا بھی مدھرے گی، چونکہ کھیتی کے بعد اسی ادھیوگ کا دوسرا استھان ہے۔

آخر میں اس امید کے ساتھ کہ میرے سنشودھنوں پر مانئے منتری جی غور کریں گے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ (ختم شد)

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): सर, हम सब इनसे एसोसिएट करते हैं।

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Thank you, Sir.

Hon. Vice-Chairman, Sir, before I start, I would like to make an appeal to you. I have never asked for extra time. If today I exceed the time-limit by two-three minutes, kindly excuse me, because the matter is very sensitive to me.

आज जो मुद्दा आनन्द जी और दूसरे आदरणीय सदस्यों ने उठाया, यह जो स्वदेशी की भावना है, 'Make in India' की भावना है, जिसको आज दोहराया जा रहा है, यह सदियों पुरानी भावना है। 110 साल पहले जब बंगाल में Anti-Partition Movement शुरू हुआ था, उस समय तीन चीजें उभरकर आई थीं। पहला, 'वंदे मातरम्' का स्लोगन, दूसरा, 'bonfire of foreign goods and boycott movent' और तीसरा, 'स्वदेशी'। स्वदेशी की भावना यहां तक पहुंची कि Scientist Dr. P.C. Roy जैसे महान इन्सान ने Bengal Chemicals खुद बनाया, साथ ही स्वदेशी की भावना से प्रेरित और अनुप्राणित होकर हिन्दुस्तान में जगह-जगह पर कॉटन मिल्स और दूसरी अन्य मिल्स बनने लगीं, जैसे स्वदेशी कॉटन मिल, बंग-लक्ष्मी कॉटन मिल, जो नेशनलाइज़ेशन के बाद एन.टी.सी. के अख्तियार में आ गईं। मैं पुराना इतिहास दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन याद जरूर दिलाना चाहता हूं।

अभी मेरे पास 2013-14 की जो एनुअल रिपोर्ट है, regarding the NTC (National Textile Corporation), इससे पता चलता है कि 103 एन.टी.सी. मिलें बन्द हो चुकी हैं, सिर्फ 23 running mills हैं। यह रिकॉर्ड थोड़ा-बहुत अलग हो सकता है, यही रिकॉर्ड मंत्री जी बताएंगे। मेरे पास जो एनुअल रिपोर्ट है, उसी के आधार पर मैं यह उल्लेख कर रहा हूं। 103 एन.टी.सी. मिलें बन्द हो चुकी हैं, सिर्फ 23 मिलें चल रही हैं। सबसे ज्यादा closed mills महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्णाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और गुजरात में हैं, एक या दो बिहार और ओडिशा में भी हैं। यह हालत कैसे बन गई हमारी 103 मिल्स बन्द हो गईं और सिर्फ 23 ही चालू रहीं? इसका मतलग तो यही है कि सरकार का इन पर ठीक से ध्यान नहीं था।

Sir, rampant corruption, mismanagement and inefficiency to infinity have led the mills to close down their shutters. And what was the fate of the labourers?

Sir, I would like to quote from another Report published by the Government. It was in reply to the questions raised in the Committee on Public Undertakings, (CoPU). On pages 1 and 2 of the Report, the NTC authorities, or the Textile Ministry, admit, "The original scheme envisaged closure of 66 unviable mills and revival of 53 viable mills. NTC has so far closed 78 mills. As on 1st June, 2013, 63,188 employees have gone for MVRS, from April, 2002 onwards, and has reduced the manpower from 90,000 to 8,214 employees." इसका मतलब करीब 82,000 मजदूरों का काम खत्म हो गया। They have been rendered jobless. This is the situation. Now, why is this Bill required? In the Statement of Objects and Reasons, it has been stated very clearly that the NTC authorities want to continue with the leasehold rights. Why? Again I am quoting from the Report of COPU at page 35, point Nos.3 and 4, with your kind permission. "NTC

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

started selling obsolete plant and machinery of its mills slated to be closed under the revival scheme approved by BIFR and also making way to sell the building debris and surplus land." I am putting emphasis on 'surplus land' because the situation is that everybody's eye is on land. The land sharks are roaming around in the corridors of power every time to have access to Government land at a throw-away price. This new Government has come with promises. I would appeal to the new Government that they should not play the role of बिकाऊ सरकार, कि हम सब बेच देंगे, माइंस बेच देंगे, नेशनल एसेट्स बेच देंगे और पी.एस.यूज़ बेच देंगे। अगर आप 'मेक इन इंडिया' आदर्श से उद्भूत हैं, अनुप्राणित हैं, तो आपको बिकाऊ सरकार का रोल प्ले नहीं करना चाहिए, बल्कि आप दूसरा रास्ता देखिए, दूसरी राह पर चलने की कोशिश कीजिए। Now, Sir, point No.4, "NTC thereafter would only start the sale of such land becoming eligible for sale, but most of the States did not give permission for sale of NTC mills' land giving one or the reason." This is very important. "NTC could not make any major headway till the sale of five Mumbai mill lands took place simultaneously, surrendering two Mumbai mill lands to Maharashtra Government and other organizations with the permission of Supreme Court in the year 2005." Therefore, there were serious objections from different States against the sale of NTC land. Why? I have submitted four amendments to this Bill. On what your Government wants to do, I have nothing to say except that if the original lesser is any State, even after an attempt on the part of the Government to revive the sick textile units if the purpose has been frustrated and it cannot go ahead with the manufacturing or production of textile in the units, in that event the land must go back to the States because after all it is the property of the State and the Central Government cannot encroach upon the assets of the State Governments. It will be against the principle of our federal character. That is why I have submitted four amendments. I would appeal to the hon. Minister to consider these amendments and if an assurance comes from the Minister that the interest of the States will be protected in the Rules, then certainly I will withdraw the amendments. With these words, Sir, I conclude. Thank you, very much.

श्री शरद यादव (बिहार) **:** उपसभाध्यक्ष जी, इस बिल पर लोगों ने विस्तार से बोल दिया है और मैं सोचता हूं कि हर तरह का पक्ष इस पर आया है। मैं इस बिल के हक़ में खड़ा हुआ हूं, लेकिन एक शर्त के साथ खड़ा हुआ हूं। यह जमीन आज नहीं तो कल मुम्बई में बिक चुकी है और यह जमीन हजारों एकड़ है। और यह पूरे शहर के भीतर और शहर के अंदर आ गई है। इसलिए बिल तो लाना जरूरी था कि यह सरकार के हाथ में तो आए। तो इसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। फिर साथियों ने बहुत से सुझाव दिए। मैं उन सुझावों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं एक सुझाव इनके साथ देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर यह जमीन भारत सरकार के हाथ में हो। अभी

सुखेन्दु शेखर राय जी बोल रहे थे कि यह स्टेट गवर्नमेंट की हो। मैं इन दोनों बातों पर सहमत हूं। लेकिन यह जमीन हजारों साल से किसानों की थी और दस्तकारों की थी। हमने दस्तकारी के सवाल को जिस तरह तबाह किया है, इस देश की गरीबी का वास्ता उससे बहुत ज्यादा है। यानी, पूरी आजादी की लड़ाई का भी लोगों ने जिक्र किया। महात्मा जी खुद दस्तकार हो गए थे, यानी देश की यह इतनी बड़ी चिंता थी। लेकिन यह दुनिया की नकल करके जो विस्तार हुआ तो वह होना चाहिए, आप बाजार को रोक नहीं सकते। लेकिन निश्चित तौर पर जो आपके पास ताकत है, आपके पास पूंजी है, आपके पास स्किल है उसे नहीं बचाएंगे तो हमारी हालत चीज के बनिस्बत हिन्दुस्तान की **...(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : आर्डर प्लीज।

श्री शरद यादव : मेरी मुश्किल यह है कि मैं बिना शांति बोल नहीं सकता।

मैं कहना चाहता हूं कि भारत के हाथ में ही कौशल है। हमारे सारे देश की संस्कृति और तहजीब का यह शरीर ही सबसे बड़ी नियामत है, मशीन नहीं। चाहे आयुर्वेद हो और चाहे दस्तकारी हो **...(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : कृपया आपस में बात न करें।

श्री शरद यादव : हम तो आते ही रहते हैं और आए हैं इसलिए कि कुछ नई बात रखूंगा इसमें। तो हमारा सारा का सारा दर्शन मशीन पर नहीं है। हम बैक टू नेचर हैं, नेचर के साथ हमारा कभी conflict नहीं हुआ और इसी के जरिए हमने अपने जीवनयापन के रास्ते खोजे। उन रास्तों में हर गांव में बाजार की जरूरत ही नहीं थी इस देश में। बाजार में हमारे लोगों को जाने की कभी जरूरत ही नहीं थी। वहीं सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, उसमें से एक कपड़ा भी था। हिन्दुस्तान में कपड़े के इतने बड़े पैमाने पर उद्योग थे कि हिन्दुस्तान का जो एक्सपोर्ट था, वह आधे यूरोप में था, पूरे गल्फ में था। यानी, हमारे पास एक थाती थी, जो अंगुलियों का हमारे हाथ में कमाल था। हमारी अंगुलियों में जो कमाल है वह दुनिया में बहुत कम है, चीन के पास है।

श्री भूपिंदर सिंह (ओडिशा) **:** आज भी है।

श्री शरद यादव : आज भी है, मैं उसी पर आ रहा हूं। यानी, सदियों से हमारे संस्कारों में, अंगुलियों में कमाल है। इसे हमने इस्तेमाल नहीं किया। आज दुनिया ऐसी बनी है जो ग्लोबल हुई है, उसमें यह है कि आदमी वेराइटी चाहता है। यानी, दुनिया का जो बहुत सम्पन्न और पूरी तरह से सम्पत्ति का हकदार बन गया है, वह नहीं चाहता कि हमारे आपके जैसे कपड़े पहने, हमारे आपके जैसे मकान बनाए। वह बिल्कुल अलग चीज चाहता है। तो इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जब मैं केन्द्र में 1989 में टेक्सटाइल्स मिनिस्टर था, अभी आप हैं, तो मैंने पहला काम किया कि जो दस्तकार लोग हैं, जो हाथ के कारीगर हैं, जो मधुबनी के लोग हैं, चाहे वे ट्राइबल एरिया के लोग हैं, चाहे वे आपके छत्तीसगढ़ में और कटक में लोहे के कारीगर हैं, यानी उनके पास लोहे की अद्भुत पुरानी कला है। वह दिल्ली हाट में हमने बनवाया। मंत्री जी, आप चले जाइए। दिल्ली हाट में जितनी भीड़ है, उतनी नए बने बाजारों में नहीं है। समाज में जितने ऊंचे तबके के लोग हैं, जो

[श्री शरद यादव]

अलग रहते हैं, अलग चलते हैं, अलग उड़ते हैं, अलग बसते हैं, वे आपको दिल्ली हाट में अवश्य मिल जाएंगे, क्योंकि वहां उनको वैरायटी मिलती है। आज का बाजार किसी भी चीज की एक सी शक्ल बना देता है, लेकिन हिन्दुस्तान के दस्तकारों में आज भी ऐसे लोग बचे हुए हैं, जो अलग रूप देते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जैसे पहले जमीन को बेच दिया, मुम्बई में बेच दिया, दूसरी जगह बेच दिया, आप इसको उस तरह मत बेचिए। या तो आप इसको राज्य सरकार को दे दीजिए या ऐसा कुछ कीजिए। मैं तो कहता हूं कि किसी को मत दीजिए, हिन्दुस्तान की दस्तकारी के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वह रोजगार से भरी हुई है, जिसका सदियों से आपके संस्कारों और शरीर में गहरा असर है। आपकी उंगलियों में ही ऐसा कमाल है, जिससे ताजमहल निकलता है, आपकी उंगलियों के कमाल से ही खजुराहो बना, जिसमें हार्ड स्टोन से बनी हुई मूर्तियां हैं। आप कोणार्क को देखिए। क्या कोई दुनिया में इस तरह के हार्ड स्टोन का ऐसा स्टेच्यू बना सकता है? आज भी दुनिया से लोग ताजमहल देखने आ रहे हैं, खजुराहो, कोणार्क को देखने आ रहे हैं। वे आपके किसी एअरपोर्ट को देखने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे एअरपोर्ट तो वहां कई बने हुए हैं। यहां आप तो बड़ी-बड़ी, ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, आप चीन चले जाइए, ऐसी बिल्डिंग्स से चीन पट गया है, यूरोप जाओगे तो वहां भी देखोगे कि पूरा पटा हुआ है। उसकी ऐसी स्थिति इसलिए है, क्योंकि दो-ढाई सौ साल तो उसने दुनिया को गुलाम रखा है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि यह जो जमीन है, इसे बेचा न जाए।

महोदय, हमारा हिन्दुस्तान का जो दस्तकारी का आंदोलन था, जो आप कपड़े से लेकर देशी और स्वदेशी की बात कर रहे हैं, वह बाजार आपके ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के दिमाग में बहुत गहरे से घुस गया है। आप लाइए, लेकिन एक बात जरूर करिए कि यह जमीन जो है, हिन्दुस्तान के उन बेरोजगारों, हर तरह से निकाल दिए गए, बरबाद और तबाह कर दिए गए दस्तकारों के लिए उससे उनका कोई ठिकाना बनाइए। उसमें आप अच्छे से अच्छा बाजार खड़ा कर दीजिए। आप देखिए, दिल्ली हाट जो है, वह सभी हाटों से ज्यादा ग्राहक लाता है, सबसे ज्यादा यहां बिक्री होती है और यहां कारीगर बैठते हैं। इस बिल का तो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जो यह जमीन आप बचा रहे हैं, यह बेचने के लिए नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपने मॉडर्न फूड बेच दिया, जैसे हमने कौड़ियों के दाम अपने होटल्स बेचे हैं। यह जमीन जो है, यह देश की संपत्ति है। यह ऐसी संपत्ति है, जिसकी हमें रखवाली करनी चाहिए, जिसे हिन्दुस्तान की हजारों वर्षों की परंपरा को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और हमें उसके लिए एक बाजार देना चाहिए। जो दस्तकार मिट गए हैं, लुट गए हैं, निकल गए हैं और आज भी घिसटते-घिसटते जी रहे हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हों, या जैसा बनारस का यहां जिक्र किया गया। हिन्दुस्तान में आज तो ऐसी कोई जगह नहीं है, जो बनारस जैसी न हो। हर जगह अलग-अलग किस्म के कपड़े बनते हैं, अलग-अलग किस्म के गलीचे बनते हैं, अलग-अलग किस्म के ऊनी कपड़े बनते हैं और इतनी मार के बाद भी लोग आज उसे बनाते हैं।

महोदय, मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं टैक्सटाइल्स का मिनिस्टर रहा हूं। कुछ लोग चाइल्ड लेबर की बात चलाते हैं। मैं कहता हूं कि संगीत सीखना बचपन में हो सकता है। क्या 12 साल का लड़का संगीत नहीं सीखता? सरोद या सितार या तबला बजाना, यह तो बचपन की उंगलियां साधने से ही होता है और ये बच्चे चाइल्ड लेबर में नहीं आते हैं। इसी तरह कपड़ा बुनने

वाले, मिस्त्री का काम करने वाले, इस तरह के दस्तकारी का काम करने वाले बच्चे, वे चाइल्ड लेबर में नहीं आते। इसलिए हमें यह भी तय करना चाहिए कि चाइल्ड लेबर में कौन आएगा? हां, होटल में काम करने वाले, घर में अन्याय के साथ काम करने वाले जो बच्चे हैं, उनको आप चाइल्ड लेबर में लाइए, लेकिन हिन्दुस्तान की जो हमारी विरासत है, पूंजी है दस्तकारी, उसको देखिए। दस्तकारी से, अपनी कारीगरी से ताजमहल बनाने वाले क्या सिर्फ बड़ी उम्र में आकर उसे बना देते हैं? वे तो बचपन में सीखे हुए लोग थे, जो ईरान से, दूसरी सब जगहों से आए। आप ऐसी दस्तकारी का कमाल उनकी उंगलियों में बचपन से पैदा करोगे, या बाद में पैदा करोगे? इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आज भी हमारे यहां दुनिया के जितने टूरिस्ट आ रहे हैं, वे आपको देखने नहीं आ रहे हैं, हजारों वर्ष पहले के जो दस्तकार हैं उनके कमाल को देखने आ रहे हैं, जिन्हें हमने भूलने का काम किया है। हमने उन्हें भूलने का काम किया और इस कारण कंगाली, दरिद्रता, भूख है और दूनिया में हम पिछड़े हुए हैं। आप इस जमीन को ले रहे हैं। यह जमीन कानपुर, मुम्बई, अहमदाबाद, कोलकाता और आन्ध्र प्रदेश के शहरों में लोग बता रहे थे। यह हर जगह है। अहमदाबाद में तो बहुत बड़ी जगह में इंडस्ट्री थी, लेकिन उज़ड़ गए। मैं मंत्री जी से कह रहा हूं कि आप इस बिल को लेकर आए हैं, यह ठीक है, लेकिन इस जमीन को दूसरी जगह नहीं बेचना। यह बेचने का भी खेल है। अभी आपको ये कह रहे हैं कि यह बिल ले आओ, जमीन हाथ में रख लो। मैं तो बहुत दिन सरकारों में रहा हूं। मुझे मालूम है कि बेचने की कैसी प्रक्रिया चलती है। पता ही नहीं चलता कि रात-रात में कब बिक गई। इसलिए इस बारे में मेरा साफ कहना है कि इस जमीन को बेचा नहीं जाना चाहिए। यह इस बिल में तो नहीं है, लेकिन ये सारी जगहें और टैक्सटाइल मिल जहां नहीं चल पा रही हैं, हालांकि लोगों ने प्रयास किया कि चलाओ, चल सकती है, तो चलाओ, लेकिन जहां मिल नहीं चल रही है, वहां जैसे 'दिल्ली हाट' है, उसी पैटर्न पर पूरे देश में, "हाट" बनाने का काम कीजिए, जिससे हिन्दुस्तान के जो बचे हुए दस्तकार हैं, उन्हें बचाया जा सके।

आज चीन ने दुनिया भर के बाजारों को पाट दिया, लेकिन उसने अपने दस्तकारों को नहीं मारा। आज वही दस्तकार उसके काम आ रहे हैं, लेकिन हमने अपने दस्तकार मार दिए। हम और चीन बराबर थे, लेकिन अब हम पीछे रह गए। आप अपने मंत्रालय में बहस करके इसे ठीक कीजिए और इस जमीन को न बिकने दीजिए। आज मैं इस हाउस में यह कहने के लिए ही वापस आया हूं कि इस जमीन के बारे में एक बिल और लाइए तथा 'दिल्ली हाट' जैसी जगह बनाने के लिए सब जमीनों को हाट बनाने के लिए दे दीजिए और हिन्दुस्तान के दस्तकारों को बचाने का काम कीजिए। इससे आप हिन्दुस्तान में अमर हो जाएंगे। हमारे देश से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, जब बाजार ठप हो गए, तब भी हैंडलूम का ही था, हाथ की दस्तकारी की चीजों का ही था। आप पता लगा लीजिए। बाजार ठप हो गया, तो आपकी सब चीजें बेकार हो गईं और आपके यहां भी रिसैशन आ गया, लेकिन आपके यहां का हाथ का बना सामान दुनिया में बिक रहा था। इसलिए, इन्हीं बातों के साथ मेरी आपसे विनती है कि आप एक नया बिल लाइए और इस जमीन को हाट-बाजार के लिए दे दीजिए, तभी इस बिल का मतलब होगा, नहीं तो इसका उद्देश्य सफल नहीं होगा। पता नहीं आप कब तक मिनिस्टर रहते हैं, यदि कोई दूसरा आ गया, तो इस जमीन को कहीं बेच न दे।

श्री उपसभापति (डा. सत्यनारायण जटिया) : नहीं ऐसा तो मत कहिए।

श्री शरद यादव : मैं आने वाले सभी मंत्रियों के लिए कह रहा हूं कि यह जमीन बिकनी नहीं चाहिए।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डा. नजमा ए. हेपतुल्ला) : माननीय उपसभापति महोदय, यदि आपकी इजाजत हो, तो मैं एक बात कहना चाहती हूं।

श्री उपसभापति : जी हां।

डा. नजमा ए. हेपतुल्ला : सर, यहां सलीम साहब ने बोला कि चायना से सिल्क आ रहा है। उन्होंने ठीक बात कही। सिल्क चायना से इम्पोर्ट होने की वजह से हमारी सैरीकल्चर की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो रही है। सैरीकल्चर की जो इंडस्ट्री कर्णाटक, बिहार, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश और पूरे हिन्दुस्तान में है, वह इसके कारण खत्म हो रही है। मंत्री महोदय, मेरे साथी हैं, मैं उनसे भी बोल सकती थी, मगर मैं हाउस में यह बात कहना चाहती हूं कि जो सिल्क वहां से आ रहा है, जब तक आप उसके वहां से अपने देश में आने को बन्द नहीं करेंगे, तब तक हमारी सिल्क इंडस्ट्री, जो हैंडलूम भी बनाते हैं, साड़ियां बुनते हैं, कपड़ा बुनते हैं, वह खत्म होती रहेगी और जो हमारी गांव की इंडस्ट्री है, जो सैरीकल्चर की हमारी गांव की इंडस्ट्री है, वह भी खत्म हो जाएगी।

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, I associate myself with the point raised by the hon. Minister.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I associate myself with the point raised by the hon. Minister.

SHRI T. RATHINAVEL (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Textile Undertakings Nationalisation Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014. At the outset, I would like to thank our beloved leader, Makkal Mudhalavar Dr. Puratchi Thalaivi Amma for enabling me to speak in this House on this Bill that seeks to help NTC and the working class. In 1974, at the height of recession found in the textile sector, many textile mills in the private sector were facing closure. In order to revive the sick mills and to help the working class and to save the mills in the private sector, the Union Government stepped in. The National Textile Corporation (NTC) was established to take over such textile mills in order to maintain the production and productivity level. This was then seen as a measure to save the textile workers in many parts of the country. Now this Bill seeks to vest with the Union Government's PSU, the NTC, all the land that was with those mills at the time of its being taken over by the NTC under Central Ordinance. I would also like to urge upon the hon. Minister to take all steps to revive all the sick mills in the State of Tamil Nadu by allotting sufficient funds for modernization and expansion of these sick units. The sick mills, referred to the Bureau of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), be taken out of it and we should take all

steps to revive them. As one who has been touched by the changes that have been taking place over the years, I would like to bring to the notice of the Textiles Minister the need to meet the requirements of the workers in these mills which have to be revived in right earnest. Unless the workers are enthused with permanent positions and with better service conditions, we may not be able to improve the productivity of every worker which is the mainstay for running a textile mill. Unlike many other shop floors of other industries, textile and spinning mills require workers contributing with utmost care. Hence, I urge upon the Government to take up the welfare of the NTC employees. I would like to point out here that the Government of Tamil Nadu, guided by our revolutionary leader and the People's Chief Minister, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, is liberal in increasing the wages and extending 10 per cent of bonus to the workers of the cooperative spinning mills in Tamil Nadu. The Centre may study this liberal approach of our Government to extend such facilities to textile workers all over the country.

I urge upon the Union Government to bring forth a package to increase the production in these areas by way of extending subsidies and financial assistance to the needy units so that job opportunities and production increase positively. I also urge upon the Union Government that in this competitive economic scene, we need to modernise all the NTC Mills spread across the country to give them a competitive edge. I hope that the Government is moving this Bill only to continue to run these mills in the interest of strengthening the Central PSUs and to safeguard the textile workers and their dependents. I would like to take this opportunity to request the hon. Minister to kindly approve the proposals sent by the Government of Tamil Nadu for the setting up of the Textile Apparel Parks in many parts of Tamil Nadu, including one at the Tiruchirapally District.

With these words, I conclude my speech and support the Bill.

श्री सालिम अन्सारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। आज माननीय मंत्री जी यह जो बिल लाए हैं, 2014 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, उसी में अमेंडमेंट के लिए यह आज आया है। चूंकि हमने 1974 और 1975 में दो ऐक्ट्स बनाए थे, तो हमारे ये दोनों ऐक्ट्स बहुत कमजोर थे। उन ऐक्ट्स के कमज़ोर होने के कारण जो मिलें बंद थीं, उनके लिए कुछ मिल-मालिक सुप्रीम कोर्ट में गए और 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको मिल की जमीन देने का फैसला दे दिया था। उसे रोकने के लिए फिर आनन-फानन में एक ऑर्डिनेंस लाया गया, चूंकि उसके बाद इलेक्शन का समय आ गया था, जिसकी वजह से यह अमेंडमेंट बिल पेश नहीं हो पाया था, तो अब यह बिल आया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह जो टेक्सटाइल बिल है, यह हिन्दुस्तान में, जहां सबसे बड़ा उद्योग खेती है, वहां दूसरे नंबर पर अगर कोई रोज़गार देता है, तो वह टेक्सटाइल है। इस धंधे में हमारे लेबर्स, वीवर्स, मज़दूर, बुनकर बड़े

[श्री सालिम अन्सारी]

पैमाने पर जुटे थे और खास तौर से उत्तर प्रदेश, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां भी इसकी बहुत बड़ी सनअतें हैं। और बहुत सी मिलें सरकार ने लगायीं, एन.टी.सी. ने भी लगायीं तथा कुछ राज्य सरकारों ने भी लगायीं, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण, सरकार की बेतवज्जही के कारण एक के बाद एक धीरे-धीरे सारी मिलें बंद हो गयीं। आज बड़े पैमाने पर दस्तकार, मज़दूर और बुनकर बेकार घूम रहे हैं। ठीक है, आज आप बिल लाए हैं। इस बिल से यह जरूर होगा कि जो बीमार मिलें हैं, जो बंद पड़ी मिलें हैं, उन मिलों की ज़मीनों को आप बचा लेंगे, लेकिन जैसा कि अभी शरद जी ने कहा, उन मिलों की जमीनों को बचाने का मतलब यह नहीं है कि फिर आप उनकी कहीं खुर्द-बुर्द कर दें। उसमें आप कुछ कीजिए। हमारे जो वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, वे बड़ी तादाद में हैं और वे सब आपकी तरफ नज़रें उठाकर देख रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। वे छोटे-छोटे गरीब लोग हैं जो रोज़ कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। इन मिलों के बंद होने से आज लेबर बहुत बड़ी भुखमरी के कगार पर हैं। वे बेकार पड़े हैं और आपकी तरफ नज़रें उठाकर देख रहे हैं कि नयी सरकार आयी है, वह हमारे लिए कुछ करेगी। माननीय मंत्री जी, आप उनके लिए कुछ कीजिए। आप बिल लेकर आए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं कि कम से कम इस बिल के मुकम्मल होने से उन जमीनों को बचाया जा सकेगा। सर, उन मिलों की जमीनें पहले तो बहुत सस्ती थीं, आज उनकी कीमत इतनी बढ़ गयी है कि सारे भू-माफिया और उस तरह के तमाम दलाल उन जमीनों पर नज़रें गाड़े हुए हैं और बहुत सी मिलों की जमीनों पर धीरे-धीरे कब्ज़ा हो चुका है, बहुत से मिल-मालिक उन पर अपना कब्जा किए हुए हैं। सरकार से मेरी अपील है कि इस बिल के पास होने के बाद आप प्रयास करिए और एक बार कोशिश कीजिए। बीच में जो 78 मिलें एन.टी.सी. की थीं, आपने हिम्मत जुटाकर उनमें से 23 मिलों को चालू किया। जब आपने उन 23 मिलों को चालू किया तो आपको फायदा भी हुआ, बड़े पैमाने पर फायदा हुआ, 2010, 2011 और 2012 में आपको फायदा हुआ। उसके बाद 2013 में आपने उन्हें बंद कर दिया कि उनमें लॉस हो रहा है। लॉस का भी कारण माननीय मंत्री जी ने बताया है कि कपास का दाम बढ़ गया, रेशम का दाम बढ़ गया, जिसकी वजह से हमें उन्हें बंद करना पड़ा। आप चार साल तो मुनाफा कमाते हैं और एक साल अगर घाटा हो जाता है तो आप मिल बंद कर देते हैं। आप उसका उपाय तो कीजिए। वे लाखों मज़दूर, जो उन मिलों में काम करते हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, आप उनके बारे में तो सोचिए कि वे कहां जाएंगे? उनका परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। आपने ये दो लाइनें कहकर उन मिलों को बंद कर दिया कि हमें लॉस हो रहा है। चार साल तक आपने मुनाफा कमाया, वह ठीक है। एक साल आपको लॉस हुआ तो आपने उन्हें बंद कर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप हिम्मत जुटाइए। आप टेक्सटाइल के क्षेत्र में क्यों झील के पानी की तरह जमे हुए हैं? आज आप देखिए, जापान और चाइना अपना कपड़ा बनाकर केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया की मार्किट्स में छाए हुए हैं। एक वक्त था, जब हिन्दुसतान का कपड़ा दुनिया के बेश्तर मुल्कों में बिकता था। यहां के बेश्तर बुनकर, यहां का मज़दूर तबका खुश रहता था और बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिलता था, लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार की बेतवज्जही के कारण ये मिलें बंद हो गयीं। हम जिस इलाके के हैं, उत्तर प्रदेश के, हमारे कुछ शहरों में दो-तीन बड़ी-बड़ी मिलें थीं। एक उत्तर प्रदेश सरकार की थी, दो एन.टी.सी. की मिलें थीं। वे भी बंद हो गयीं। बड़े पैमाने पर जो गरीब बुनकर

हैं, पहले सरकार उनको सूत देती थी, लेकिन आपने उन्हें सूत देना बंद कर दिया। गरीब बुनकर सूत लाता था और साड़ी, धोती, गमछा तैयार करता था। सरकार उस माल को खरीद लेती थी और उसके बदले में उसे 70 परसेंट पेमेंट तथा 30 परसेंट मैटिरियल दे देती थी। गरीब बुनकर खाते थे, जीते थे, उनका परिवार चलता था, लेकिन सरकार ने वह काम बंद कर दिया। अब छोटा बुनकर, जिसके पास पूंजी नहीं है, जिसके पास ट्रेक्टर नहीं है, वह मंडियों में अपना माल लाकर नहीं बेच सकता। आज आधुनिक जमाना है, टेक्सटाइल का जमाना है, बड़ी-बड़ी मिलें हैं, उन बड़ी मिलों के सामने, जो छोटे-छोटे वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, वे बेचारे नहीं टिक पाते। सरकार उनको पुश्तपनाही देती थी, लेकिन सरकार ने वह भी बंद कर दिया। आज पूर्वांचल के इलाके में, चाहे खलीलाबाद हो, बस्ती हो, भदोही हो, मऊ हो, बनारस हो, इन तमाम इलाकों के बुनकर आज भुखमरी के कगार पर हैं, वे बेचारे रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं, जबकि यही सनअत, टेक्सटाइल के क्षेत्र में यही वीवर्स, यही बुनकर अपनी साड़ियों के माध्यम से, अपने कपड़ों के माध्यम से इस देश की पहचान को बनाते थे।

(श्री उपसभापति *पीठासीन हुए।)*

जैसा कि अभी डा. नज़मा जी ने कहा कि हम कपास बाहर से लेते हैं, हम रेशम बाहर से लेते हैं, पहले किसान कपास पैदा करता था, रुई पैदा करना था और सरकार उसे खरीदती थी। अब सरकार रुई भी नहीं लेती, कपास भी नहीं लेती। अब किसान भी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इस देश में रेशम बनता था, उसी रेशम से हम रेशमी साड़ियां बनाते थे। जो रेशम कीटाणुओं से पैदा होता था, अब वह उद्योग भी बंद हो गया। **...(समय की घंटी)**... सारा उद्योग चौपट हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी, आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जमीनों को बचा लीजिए। आप वहां पर बुनकरों के लिए कढ़ाई केन्द्र खोलिए और कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स खोलिए। अब आधुनिक ज़माना आ गया है, अब कम्प्यूटर के माध्यम से साड़ियों के डिजाइन्स बनते हैं। जो गरीब वीवर्स हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनके लिए कुछ कैम्प खोलिए, कुछ उनको सिखाइए, कुछ उनको ट्रेनिंग दीजिए ताकि ये गरीब बुनकर, गरीब परिवार दुनिया में मंडियों का मुकाबला कर सकें और अपना जीवन-यापन कर सकें। इन्हीं चंद अल्फाज़ के साथ, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया।

श्री उपसभापति : धन्यबाद। डा. टी. एन. सीमा।

DR. T. N. SEEMA (Kerala): Sir, this Bill has just one objective which is to continue with the leasehold rights vested in the National Textile Corporation on completion of the leasehold tenure. Since the content and intent of this Bill has nothing objectionable, my Party, CPI(M) supports this Bill. The cities like Mumbai, Gujarat and many other cities had a rich history of textile production, which was the golden era of textile industries and mills. But in the last many decades hundreds of mills have been closed down and turned into luxury apartments, residential estates and shining malls in cities like Mumbai. Most of the mills are in the heart of the cities. So naturally, developers and real estate people are eyeing on the prime land. There are many reports of irregularities in the use and sale of the land of several mills. So, NTC needs to be very cautious in the dealings of land and should strictly ensure that no fraud will be played.

[Dr. T. N. Seema]

Sir, NTC has been implementing the BIFT-approved revival scheme from 2002. As part of this, NTC has so far closed more than hundred mills. The fund for modernization was mobilized by selling the assets or land of sick mills which are already closed down. But the main thrust of modernization was to reduce the number of workers. NTC has reduced the number of its employees from 80,000 to about 8,000. That means a large share of funds meant for modernization has gone to the modified VRS scheme. Thus the modernization process by NTC has become a job killing process. This modernization process should be a process of expanding the capacity of NTC. Otherwise, the whole exercise will be futile. Sir, there is enough scope for expanding the production capacity of NTC. The per capital cloth available in our country is one of the lowest as compared to the global standard. It is a shameful situation. The per capita cloth availability is only 12 yards. So, there is enough scope for expanding the capacity. As part of modernization, NTC should take the responsibility to provide best-quality textile products at affordable prices to common people. Sir, there is a large scope of improvement in the textile industry in India. The Indian retail market provides plenty of opportunities. What is the experience of marketing in NTC? Last year, an MoU was signed between NTC and NHDC to boost the handloom productivity by using the NTC 84 outlets. Sir, what is the status of that joint venture? What are the plans to make NTC a more efficient player in the Indian and international markets? Sir, has NTC done any analysis of the condition of the mills which were included in the revival project? Out of 28 mills, which were listed for modernization, four are from Kerala. One of those mills is in Thiruvananthapuram, the Vijayamohini Mills. I am also from that place. In the last eight years of modernisation process, it helped the mill to achieve good productivity and better facilities. But, there is much scope for expansion. Now, I think, it does not have much scope for expansion.

The actual requirement of manpower in Vijayamohini Mill is 363 permanent workers for full production. The deficit of worker force is managed by appointing casual labourers on daily wages. Now, the company has almost 170 causal labourers on the roll. That means, almost half of the employees are on causal basis. So, there is no need to say that these employees are denied the social security and labour protection since they are not regular employees.

Sir, the NTC should ensure that, in the name of modernisation, workers are not deprived of their rights. Sir, scarcity of labour is prevailing in many places, including Tamil Nadu. Sir, Tamil Nadu and Andhra Pradesh have a rich tradition and culture of textile industry. But, they are also facing many challenges now. Many mills under the revival scheme need further modernisation. I am saying this because after the first stage

of modernisation, in the last eight years, their performance is declining. I know the experience of mills in Kerala where the performance is declining. So, there is a need for new kind of machinery with better technology for these mills.

Sir, there are other kind of mills which had a bitter experience, like Parvathi Mills in Kollam. Sir, you also very well know about that. This mill was taken over by the NTC years back. Later, it was included under PPP model for its revival. But, nothing has happened. I think tender was floated. But, nothing has happened. Now, this mill is almost closed. There is no work. Unfortunately, neither NTC nor the State Government is doing anything at all.

Modernisation programme in NTC should be on continuous basis to meet out the market challenges by ensuring quality product for both local and international markets.

Sir, the textile industry itself is ailing due to current trend of high raw-material cost and considerably low price for finished products. The economic policy of the Government is not protecting domestic producers or farmers. We know about it. Import of cheap textiles from other countries is a big challenge to the domestic textile sector. Hon. Najmaji has also pointed it out. So, giving full power of selling the lease land only to NTC would not solve the problems in the textile sector if the Government sincerely wants to make textile sector to grow, take necessary measure to strengthen the domestic producers starting from cotton and jute farmers, expand the modernisation process and intervene in the market.

With these points, I conclude. Thank you.

SHRI A.U. SINGH DEO (Odisha): Thank you Mr. Deputy Chairman, Sir. Sir, the purpose of this amendment is to plug the loopholes in the existing law. And, the reason behind the proposed amendment, as per the Bill, is that the nationalisation of the textile undertakings, a large sum of money have been invested with a view to making the said textile undertakings viable. सर, पहले हम NTC का ट्रेक रिकार्ड देखें। उन्होंने 1968 में 119 सिक टैक्सटाइल मिल्स लीं, फिर और मिल्स लीं। उसके बाद उन सिक मिल्स को चलाने की कोशिश की। उसके बावजूद 78 मिल्स बंद हो गईं। अब 24 मिल्स चल रही हैं। सर, क्या इसमें हजारों वर्कर्स का नुकसान नहीं हुआ? जो टैक्सटाइल वर्कर्स थे, वे बेरोजगार हो गए। उनके लिए सरकार की क्या सोच है? यह जो एन.टी.सी. वेबसाइट है, यह कहती है कि मॉर्डनाइजेशन के लिए 1391.09 crores खर्च किए गए। Total area of land, जो उन्होंने बेचा है, जो 1533.09 crores है, इसमें उनको 6551 crores मिले और इन्होंने मॉर्डनाइजेशन में 1391.24 crores खर्च किए। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 5,200 करोड़ रुपये, जो खर्च नहीं हुए, जिनका हिसाब नहीं हुआ, वे कहां गए? मंत्री जी उसका हिसाब दें। एन.टी.सी. का ट्रैक रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं है, इनके intentions अच्छे थे, एन.टी.सी. को दे दिया गया, उन्होंने चलाने की कोशिश की,

[Shri A.U. Singh Deo]

लेकिन जब चला नहीं पाए, तो वे वही कर रहे हैं, जो प्रिवियस मिल ओनर्स करते थे। ये जमीन बेच रहे हैं। इनकी self-financing schemes में जो financial viability है, उसमें ये और जमीन बेचना चाहते हैं। इनके पास 641.98 acre free-hold land है, lease-hold land 593.14 acres है और total surpuls land 1235.12 acres है। ये इसको भी बेच देंगे। इन्होंने जो पहले बेचीं और अब जो इसको बेचेंगे तो क्या इससे हमारी टैक्सटाइल मिल्स चल पाएंगी? मंत्री जी हमें समझाएं कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है? यह ठीक है कि हम बिल्डर्स को समर्थन नहीं देते, उनके पास ज़मीन नहीं जानी चाहिए। इन्होंने यह अच्छा किया है कि एन.टी.सी. के स्ट्रेन्थन करके लेने की सोची, पर ये इसको चलाएंगे कैसे? ये चाइना से, थाइलैंड और अन्य जगहों से, यहां से हमारे सामने यह टैक्सटाइल कंपीटीशन आ रहा है, उनसे कैसे कंपीट करेंगे? मंत्री जी इसका ब्लूप्रिंट बताएं, समझाएं। क्या ये बिना ब्लूप्रिंट बनाए ही टेक-ओवर कर गए या इन्होंने टेक-ओवर करने की सोची? सर, मेरे पास ऐसे कई instances लिखे हुए हैं, जिसमें जब इन्होंने प्राइवेट ओनर्स से लेना चाहा, I am not batting for the private owners or for the mill owners. I am not supporting them. But, मैं factual instances देना चाहता हूं। एक पोद्दार मिल है, मुंबई में और भी ऐसी मिल्स हैं, जिनसे इन्होंने mis-management by loss के ऊपर मिल्स ले लीं। But they were struck down by the highest court, the Supreme Court. To circumvent that, they have brought this Ordinance and this particular Amendment. Sir, the means justify the end. ठीक है, जो भी है, उन्होंने ली हैं, पर क्या ये यह बता पाएंगे कि वहां पर हमारे जितने वर्कर्स थे, जो बेरोजगार हुए हैं, who have lost their jobs, who are dying of poverty, what is the plan of the Government? Are they going to take them over in the new plans? Do they have a list of these people, who were working there earlier? Are they going to take them over? ...**(समय की घंटी)**... सर, थोड़ा टाइम और दें। मैं जानना चाहूंगा - अब आपने दो-तीन बार घंटी बजा दी है, इसलिए मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, मैं मंत्री जी से खाली नहीं प्रश्न करूंगा कि आप बताएं कि हमारे जो jobless workers हैं, वे कितने हैं, आप उनको कैसे reinstate करेंगे, उनके बारे में आपका क्या प्लान है आपका ब्लूप्रिंट क्या है? आप जो यह कहते हैं कि after this Ordinance is over and the land is secure with you, NTC will not start selling the land as you have been doing in the past and that the land will remain with you. Thirdly, a good suggestion has come from one of my elder Members here that in case the NTC fails to profitise the textile mills owned in different States, then they must devolve them back to those States. That is a must. Sir, I want to end by saying that this Government's प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई रेट्रोस्पेक्टिव लॉज़ नहीं आएंगे, कोई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेज़ नहीं लगेंगे, तो मैं कहूंगा कि यह जो अमेंडमेंट है, यह रेट्रोस्पेक्टिव है। But, as I have said, means justifies the end and I would be very grateful to the hon. Minister if he could tell us where the balance money has gone, what he would like to do, to reinstate these workers who are jobless today and also what is the blueprint for making NTC profitable in future, in comparison to China in supply of material, in comparison to Thailand, Ceylon, etc.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much, Mr. A.U. Singh Deo. Shrimati Gundu Sudharani.

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI (Telangana): Sir, thank you very much for permitting me to speak on this Bill which is close to my heart as I myself hail from a weaving community and closely seen the troubles and turbulence in the lives of weavers and workers who have been striving hard to earn two square meals a day.

Sir, I wholeheartedly support the Bill moved by the hon. Textile Minister. The objective was noble when the Government had taken a decision to nationalize 119 mills not only to protect the workers but also to give a fillip to cotton and cotton-made cloth and also to compete with synthetic yarn. But, unfortunately, we are losing ground to private mills not only in manufacture, adopting technology, but also in marketing cotton products.

I agree with the hon. Minister that the Bill is not to sell the land under NTC which runs into 1,250 acres located in prime areas of the country but to revive the left out mills. It is good that nobody has objected this Ordinance, because this Ordinance has been issued in the interest of the workers and mills and to shield NTC from rent control laws that would have been used to evict some of the sick textile units.

Sir, taking advantage of this debate, I would like to bring to the notice of the hon. Minister a few issues relating to my Warangal district in Telangana region. In 2004, the then CM, Shri N. Chandrababu Naidu, announced setting up of an Apparel Textile Park in place of Azam Jahi Mills to protect the weavers. Thirty acres of land has been allotted to this Park by the TDP Government. But, unfortunately, after the change of Government nothing has been done. But, later, the Government of India has sanctioned a Textile Park at Warangal in the premises of the erstwhile Azam Jahi Mills, which was taken over by NTC in 1974 and declared sick in 1993, with a total outlay of ₹ 12.80 crore under the Textile Cluster Infrastructure Development Scheme with an objective to provide employment to 8,000 workers directly and 2,000 workers indirectly. But, after that, I don't know what has happened to the proposal. I request the hon. Minister to look into it and direct the officials concerned in the Ministry to coordinate with Telangana Government and see to it that the Textile Park becomes a reality for the people of Warangal and Telangana region.

The next point I wish to make is that the former Textile Minister has assured in September, 2013, at Bhongiri, Telangana, that he would provide ₹ 15 crore for development of a handloom park at Bhudan Pochampalli. Sir, it has a capacity of 2,000 looms, but now only 150 are running. This is resulting in problems for weavers in the park. So, I request the hon. Minister, as per the above assurance, to release money immediately which will help to increase the looms capacity to 2,000 and bring light in the lives of weavers.

[Shrimati Gundu Sudharani]

Sir, in Telangana region, Warangal is famous for cotton production. A proposal has been submitted for setting up a Composite Cotton Textile Mill by NTC in Warangal district. Warangal is the highest cotton producing district in the State and it has many weavers. Land is available and the Government of Telangana is willing to provide necessary land free of cost for this. So, I request the hon. Minister to place this before the Board of NTC for its approval for setting up a Composite Cotton Textile Mill in Warangal district.

The next point I wish to mention is about the proceeds that the NTC has accrued through sale of NTC land. NTC has more than ₹ 6,500 crores. I agree that NTC has paid some money for VRS of its mills. But, if you look at the amount that has so far been spent on modernisation and revival, it is only ₹ 1,300 crores. So, I would like the hon. Minister to give us the details of amount spent on VRS, modernisation of each mill and the status of mills that are modernized. Sir, without the captain, the ship becomes directionless. In the same way, the NTC does not have the regular CMD. That is also creating problem, particularly in modernizing the mills. So, I request the hon. Minister to immediately take steps for appointment of a regular CMD for the NTC.

Sir, I have to make one more point. During the UPA Government, the R.R.R. Scheme was introduced, but those funds are not fully utilized and most of the weaver-societies are not benefited from that. The funds are still in banks. Most of the weaver society buildings in Telangana region are in a ruined state. The weavers are not having even place to weave. The weavers are so dependent on it. I don't know how far the benefits of the R.R.R. Scheme were passed on to the weavers by that Government. At least, I hope, under this Government, everything will happen very well. Sir, with these observations, I once again support the Bill moved by the hon. Minister of Textiles. Thank you, Sir.

DR. ASHOK S. GANGULY (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, I grew up in Bombay, Mumbai now, and I watched with great interest the rise or fall of the textile industry in that city. The destruction of the textile industry in Mumbai was jointly undertaken by a famous trade-union leader, who is no more, and who was an hon. Member of this House, and the textile tycoons of those days.

Sir, through you, I want to know from the hon. Minister that by bringing about this amendment, how many textile workers, who were rendered redundant and destitute belonging to the Konkan region, have been compensated. How many mill-owners or their progenies who lead a five-star life in that city have been declared or are being investigated as wilful defaulters? What has been the history of the NTC in reviving, improving

profitability and generating employment in the mills that are put in their charge? They are known to be sincere, but incompetent. Sir, through you, I want to know from the hon. Minister, what the Government proposes to do with the nationalized lands because land is gold in Mumbai, and there is a nexus between landowners and builders. What do you propose to do with the Supreme Court's rulings on returning some of these lands, and in other cases, where textile mills were either destroyed in fire or by vagrants and converted into multi-storey offices? What do you propose to do for that? You have a hugely wealthy industry with a poor record of performance. You are in-charge of a portfolio, hon. Minister, where a lot of crime has been committed. Therefore, just by bringing in this amendment, criminals would not be brought to justice, the victims would not be compensated, and arbitration remains in the hands of an incompetent intermediary.

Sir, a lot of things have been said about the textile industry. I do not wish to repeat those things. But I would like some answers because, I think, it is a shame, historically it is a shame, that those who committed crimes continued to enjoy the fruits of their criminality, and those who are the victims are forgotten while we continue to debate endlessly. I wish the best to the Textile Minister. Thank you, Mr. Deputy Chairman.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (Odisha): Sir, in the limited time allotted to me, I will make just one or two points because already so many speakers have spoken on the issue, on different dimensions of the issue. First is, when nationalisation took place first time, more than four decades ago, at that time, the Prime Minister, Mrs. Gandhi in 1968 needed the support of the Leftists. So, the nationalisation was particularly done because of the Leftist pressure. When nationalisation was done, the corruption due to which these textile mills had been made sick, was not gone into. Those people made their textile mills sick, minted money, got out and the Government took over. I will give one example. There is only one mill which NTC has taken over in Odisha. I know the case intimately enough. They bought second hand machinery, passing it off as new machinery and everybody colluded in that corruption. That old machinery in no time became junk and the Government got junk. Government tried to, through the NTC, modernise and modernised half-heartedly. It never became really a working unit. NTC's record has been mixed. It is not good years, bad years, four years of profit and one year of loss. My friend said, "Why do you close down when there is one year of loss?" Several years of loss, very few years of profit, that is the record of the NTC. And whose land is it, my second point is emanating from this. Okay, to negate a court order, today we are faced with air Ordinance and then a Bill to validate it. Now whose land is it, anyway? I come to a fundamental issue, Mr. Deputy Chairman, here the fundamental issue is this; when you take the land for any industry, forget the textile mills; you take State Governments'

[Shri Pyarimohan Mohapatra]

4.00 P.M.

lands. You take it free of cost or at a subsidised rate. Then you take larger amount of land than what is necessary and later on you sell off those lands at very high prices. What for? Lands have been either given by the Government or have been acquired and given. As early as in 1971; Government of lndia, Bureau of Public enterprises issued a circular that no State Government shall give land at less than the market rate to Central undertakings as otherwise it is perverting the balance-sheet, the viability, the IRR. All these things are perverted because you do not take into account the real investment. In spite of that, the Government of India went on making States fight to give land free. We are the Council of States. This is something on which we have to unite to see that the Government does not do this blunder again and again. My friend, Shri Singh Deo, just pointed out how much of land has been sold. It is sold and only one-fourth of it is invested. That is the story of divestment. Take land from the State Governments, call it surplus land, sell it off and when you divest that much, you do not reinvest for that particular industry. You want to make up the budgetary deficit of the Central Government. The States are not here to fill up your deficit and then you keep on telling the States, 'look, we are not going to give you any more money, you try to raise your resources, you cannot live on grants.' This should not go on. This is my appeal, to all my friends here, from different States, to press upon the Central Government to stop playing this game. The Government must take it for any industry, for any requirement, at market rate. And, if the Government has taken for social requirement, for educational purposes, free of cost, then it becomes the land of the President of India. Then, they sell that at very high rates. In Kolkata, lands of Central undertakings have been sold at very high rates, saying that this is needed for stopping the sickness. Who had made them sick? Not the State Governments. ...*(Time-bell rings)*...

One last point, which somebody has already made. But I want to expand it in half-a-minute. ...*(Time-bell rings)*... The Textile Minister must now think of, not the so-called needs of urbanization, but his own Ministry's programme of integrated textile park, his own programme of clusters. Let it happen in those mills and provide employment opportunities and see that viable units come up.

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, at the outset, I would like to say that we are really very, very grateful to late Shrimati Indira Gandhi who had taken a decision to nationalise some textile mills four decades ago. Why did Shrimati Gandhi took that decision at that point of time? She took that decision for three reasons: one,

for survival of the workers; two, to increase the textile units and the textile production in a proper manner; three, for diversification. Unfortunately, for the last few decades, we have been witnessing that all these textile industries, either in Kolkata or in Mumbai or in Ahmedabad, were practically being controlled by some retired IAS officers or the retired State Service officers. They were supreme in these textile mills. They were the Chief Executive Officers or the General Mangers or the Managing Directors. These people had no commitment for the industry. They had only the sole intention to somehow squeeze money out of them and leave that place. We have several times asked to bring in the technocrats. But, unfortunately, that did not happen. While the Minister has introduced this Bill, I would like to know what his future planning is. That should be made very clear here. Is he going for any diversification programme? If yes, what kind of diversification does he want to introduce? Many hon. Members have said that we are facing a serious challenge from China and other countries. That is true because their textile industry is running very effectively. The textile industry of China is producing excellent quality of textile. But, unfortunately, in our country, we have failed to do so. So, I feel, a time has come when the Government should think about this very seriously. It is not only the foreign goods, but the synthetic stuff is also a big challenge to the cotton textile. All those who are producing synthetic stuff have a very strong lobby. I do not know how the hon. Minister of Textiles will combat with the synthetic stuff lobby and protect our cotton textile industry.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN) *in the Chair*]

It is true that cotton textile industry is our property, our pride. It is even connected with our freedom movement. *Swadeshi bhavana* is totally connected with the textile mills. But nowadays, it is really unfortunate that we are not giving proper attention to this industry. The hon. Minister has said that he has the intention to protect the land. It is good. He must protect the land. I have seen many textile industries in Kolkata, and also in surrounding areas. Some are deserted. Many mills have been closed. No worker is working there. Some of the Members said: Has the Government prepared any list of the people who were working in those textile units? I am sure they do not have any statistics like this. I urge upon the hon. Minister to collect the names of the workers who were displaced and who are now jobless.

Number two, I would like to ask the Minister how and when he is going to protect the land. How will it be utilized? Do you have any plan as to how this land will be utilized? We have large tract of lands. Some of the lands were occupied by unauthorized persons also. I do not know how the Minister will take off this land from these unauthorized

[Shri P. Bhattacharya]

persons. In this context, he will have to talk to the State Government. Land belongs to the State Government. What is the intention of the State Government, that also has to be looked into. Otherwise, it will be very difficult for the Central Government to start any project there.

Sir, again, I would say that this is a very important industry in our country. Thousands of workers were displaced. I do not know how they will be taken back and what process will be applied for them.

Sir, the Central Government approved a scheme sanctioned by the Board of Industrial and Financial Reconstruction for the revival of sick textile mills under the Sick Industrial Companies Act, 1985. Mr. Minister, please listen to me. Sir, through you, I would like to inform the hon. Minister that this Act has also to be amended. If we do not amend this Act, it will be very difficult even to protect your 26 or 28 new model mills.

Lastly, I would like to tell you that the NTC has taken the decision of modernizing a few mills in the country. But in West Bengal, they have proposed only one textile mill, that is, Aarti Textiles. I would urge upon him to look into this matter so that other textile units are also taken up.

With these words, I would like to conclude. Thank you very much.

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात) : सर, टैक्सटाइल सिक यूनिट, जो बीमार यूनिट हैं, उनकी लीज समाप्ति के बाद, BIFR द्वारा अधिकृत योजना के अन्तर्गत यह बिल लाया गया है। मैं इसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, हमारा देश शुरू से, 17वीं और 18वीं सदी से लेकर अब तक वीविंग और स्पिनिंग के लिए पहचाना जाता था। हम लोग बहुत एक्सपोर्ट करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कपड़ों के बारे में गुजरात अव्वल नंबर पर था। दुनिया में अहमदाबाद को मेनचेस्टर के रूप में जाना जाता था। अहमदाबाद एज वैल एज मेनचेस्टर। सर, अब तक इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

सर, हमारे देश में यह इंडस्ट्री ऐसी है जो एग्रीकल्चर के बाद रोजगार देने वाली दूसरे नंबर की इंडस्ट्री है। हमारे एक दोस्त ने कहा कि इसमें 35 मिलियन एम्पलाईज़ काम करते हैं। देश में फैक्ट्रियां बन्द होने के बाद भी आज 35 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सर, एग्रीकल्चर के बाद यही एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें हम देश के हजारों और लाखों को रोजी-रोटी दे सकते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसकी परवाह नहीं की।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं। कि जर्मनी और इटली के बाद हमारा देश एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर पर आया है, लेकिन दुख की बात यह है कि चायना फर्स्ट नंबर पर है और सेवन टाइम्स हम से आगे है। हमने 2 करोड़ यू.एस. डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, तो चायना ने 14

करोड़ यू.एस. डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। आज चायना हमारे लिए एक लाल बत्ती के समान है। चायना में भी मजदूरी कम नहीं हो रही है, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। सर, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल जो आज लाया गया है, अगर इसे पहले लाया गया होता, तो जो फैक्ट्रियां आज बन्द हैं, वे बन्द नहीं होतीं। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग आज भूखों मर रहे हैं।

सर, मैं आपको आज से 12 साल पहले की बात बताना चाहता हूं। हमारे गुजरात में उस समय पूरी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब गुजरात के सी.एम. थे, उन्होंने सभी मिल वालों को बुलाया और उनकी बातें सुनीं और उनकी समस्याएं दूर कीं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज सूरत में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हब बन गया है। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि शिफॉन की साड़ी, जो पहले 800 से 1000 रुपए में मिलती थी, वह आज 100, 150 और 200 रुपए में मिलने लग गई है। आज देश के कई भागों के मुकाबले गुजरात एक्सपोर्ट में अव्वल नंबर पर है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे देश के दूसरे प्रदेश हैं, जैसे कि यू.पी. है या राजस्थान है, वे भी एक्सपोर्ट में ऊपर आएं। राजस्थान के भीलवाड़ा को मॉडर्न सिटी और टैक्सटाइल सिटी कहा जाता था। आज भीलवाड़ा की टैक्सटाइल यूनिट्स सिक पड़ी हैं।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कोई भी फैक्ट्री खोलता है, जाइंट वैंचर बनाता है, तो उसे एक यह गारंटी चाहिए कि उसकी यूनिट चलेगी, सिक नहीं होगी। आज लीज की प्रॉब्लम हो गई है। लीज खत्म हो गई, लेकिन उसे आगे बढ़ाने का अब तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। लीज वाले सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वे जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जब यह जमीन गवर्नमेंट के पास आ गई और अब सेंट्रल गवर्नेंट के पास है, तब एज.ए. कस्टोडियन, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अक्तूबर महीने में एक बुलेटिन जारी किया - "The Narendra Modi Government's ordinance promulgated last Friday would help block attempts to strip nationalized textile units of prime real estate worth ₹ 200 billion across 14 States, a top Government officer said. The ordinance makes it clear that the National Textile Corporation (NTC) only holds the land as a custodian..." सर, इसे पहले किया जाना चाहिए था। मैं इसके लिए दुख व्यक्त करता हूं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन हमें इसके लिए पहले शुरुआत करनी चाहिए थी। आज हमारे मंत्री महोदय, यह अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके मूल में employment की बात है। आप इसके मूल में जाएं तो इससे गारंटी मिलेगी, लोगों को लीज़ प्राप्त हो जाएगी, लीज़ होने से इनका पट्टा रिन्यू हो जाएगा और रिन्यू होने के बाद वे आराम से बिजनेस कर सकेंगे।

सर, जो समय मुझे दिया गया है, वह अपर्याप्त है, इसलिए मैं दो-चार बातें मंत्री जी से

[श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल]

कहना चाहता हूं। जो यूनिट बंद पड़े हैं, जो मिलें बंद पड़ी हैं, गुजरात, यू.पी., बिहार, बंगाल या राजस्थान में जो यूनिट बंद पड़े हैं, उनके जो लेबरर्स हैं, जो कारीगर हैं....सर, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां कैसे कारीगर होते थे। जब अखंड भारत था, तो अंगुली में पहनने की जो रिंग होती है, तब उसमें से साड़ी निकल जाती थी। जो कोकोनेट होता है, जिसका पानी हम पीते हैं, पूरी साड़ी उसके अंदर समा जाती थी, एक छोटे से कोकोनट में। हमारे कारीगर ऐसे-ऐसे काम करते थे, लेकिन आज वे कारीगर बेकार हो गए हैं, उनका परिवार बेकार बैठा है। लैंड पड़ा है, लैंड बेचने के लिए मिल-मालिक खड़े हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे जो कारीगर हैं, वह लैंड उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए इस्तेमाल हो, इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, weaving is a precious human skill. Textile industry was the first industry started by men. Only after the textile industry, other industries came into existence. So, I am very proud that I am speaking on this Amendment Bill. In order to avoid eviction and thereby making it explicit that the ownership of land will be with the Central Government, this Bill is introduced. I hope that our dynamic Textile Minister will do a good job. So, I welcome and support this Bill. Through this, Government has accorded some status to National Textile Corporation. This would have been, done very early. Let it be so. It is better late than never. But I would like to clarify certain points to my Congress friends. Our Telangana friend spoke enormously about this subject. He mentioned about Mumbai, Kolkata, Varanasi and so on, but he has not mentioned about Tamil Nadu and Coimbatore industries. Coimbatore is called 'Southern Manchester'. In 1968, our brave leader Mrs. Gandhi formed NTC. But before that in 1967, our great leader, Anna, in his DMK election manifesto said that he was going to bring sixteen Tamil Nadu textile mills under Government administration. He promised it to the people in 1967. And in 1968 on the floor of Tamil Nadu Assembly, he promised that he was going to form Tamil Nadu Textile Corporation. But in 1969, his health did not allow him to do that. After him my leader Thalaivar Kalaignar took charge in 1969. In the Budget of 1970, he granted ₹500 crore to form Tamil Nadu Textile Corporation. He undertook sixteen mills and ran them properly. After 1972, all the sixteen mills were taken over by the Central Government, by NTC. Now, out of these sixteen mills, only seven are running; only seven are operational. Rest of the nine are closed. Even out of these seven, five mills are on the way to 'close' now. So, at this juncture, all

over India, I think out of 104 mills, twenty seven mills are running now. The remaining are closed. So, we must be very careful with this amendment. It should be helpful for the textile industry. 'Make in India', 'Made in India', be it any form of India, it should not be changed to real estate business. The textile business should not be changed to real estate business. So, we must be very careful.

At this juncture, I take this opportunity to highlight the labour issues which are most prevalent in NTC. Recently, the Ministry had informed this august House that under revival plan, approximately 65,000 employees were to be given Modified Voluntary Retirement Scheme, *i.e.*, 63,295 employees have opted for MVRS at a compensation of ₹2,378.75 crore. But this compensation is not enough. It should be doubled. You are going to take these mills. In the Coimbatore city mills alone, the land is worth about ₹10,000 crore. But, all over India, the compensation is ₹2,378.75 crore! Give share to labour also. Provided the worth of property, you can divide it and give the share to the people and their families. I wonder, whether it is a voluntary retirement scheme or wantonly retiring scheme. That also I want to know from the Government. The textile industry is human labour intensive. Before declaring any industry sick, it is imperative on the part of the Government to take care of the interests of the labourers. If they are thrown out, their entire family comes to the street. That is what Congressmen told here. Their entire future becomes a question mark. This has to be taken care of. I believe that our Minister and our Prime Minister will take care of the labour issues. By this assurance, I am supporting the Bill. I am welcoming the Bill. I am appreciating the Bill. Thank you, Sir.

श्री मधुसूदन मिस्त्री (गुजरात) : सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरी पार्टी इस बिल को सपोर्ट कर रही है, इसलिए मैं भी इसको सपोर्ट कर रहा हूं। सर, यह बिल मुझे मेरे भूतकाल के अंदर ले जाता है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं, जो परिवार उस जमाने में मिल की कमाई के ऊपर सम्पूर्ण आधार रखता था। मेरे मामा टेक्सटाइल के अंदर वीवर थे। जब मैं वहां पर उन्हें टिफिन ले जाकर देता था, उस वक्त उस टेक्सटाइल मिल से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। जब मैं जूनियर और सीनियर बी.ए. में था, उस समय मिल के अंदर जब रेग्लुर वर्कर्स नहीं आते थे, उस वक्त बदली वर्कर्स के लिए जाते थे। उन बदली वर्कर्स के अंदर मैंने प्रिंटिंग मास्टर के हेल्पर के रूप में, कलर मिक्सर के रूप में काम किया। मैंने पानी पिलाने का भी काम किया, peon का भी काम किया और अन्य जो अलग-अलग categories होती हैं, उनमें भी काम किया और मिल से मैंने बोनस भी लिया। वह मिल आज बंद हो गयी है। सर, पहला शॉक हमें सबसे पहले 1967 के अंदर लगा जब अहमदाबाद शहर में दस टेक्सटाइल मिलें बंद हो गयीं। जो टैक्सटाइल की 80 कम्पोज़िट यूनिट्स थीं, जिनके अंदर ब्लो रूम, ब्लो रूम से फ्रेम, फ्रेम से स्पिंडलिंग, स्पिंडलिंग से साइज़िंग, साइज़िंग से ड्रॉइंग, ड्रॉइंग से वीविंग डिपार्टमेंट और वीविंग डिपार्टमेंट से फिर प्रिंटिंग में जाता है और उसके बाद वॉशिंग और स्टैंपिंग होकर माल बाहर

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

निकलता है। ये उसके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं। उसको एक composite unit कहते हैं। ऐसे 80compositeunits उस पूरे शहर के अंदर थे, उनमें करीब डेढ़ लाख मजदूर काम करते थे। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद में, उस टैक्सटाइल मिल में गांधी जी की बनाई हुई यूनियन, जो मजदूर महाजन संघ कहलाता है, उसके अंदर भी मैंने दस साल ट्रेड यूनियन वर्कर के नाते से काम किया है। टैक्सटाइल के साथ मेरा नाता बहुत पुराना जुड़ा हुआ है। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था, उस वक्त 1967 में एक साथ 10 टेक्सटाइल मिल्स बंद हुईं, तो एक बड़ा तहलका पूरे शहर के अंदर मच गया क्योंकि एक साथ हजारों मजदूर बेकार हो गए। उन मजदूरों को काम देने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं थी। इतने बड़े पैमाने पर मजदूर बेकार हुए, उनको उस समय कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। उनकी प्रोविडेंट फंड की रकम चली गई, उनकी ग्रेच्युटी की रकम चली गई थी, उसके बाद लैंड के ऊपर किसी का लिटिगेशन था, बैंकों का कर्जा था और मिल मालिक लोग बैंक का पैसा वापस नहीं देते थे, इलेक्ट्रिसिटी वालों ने बिजली काट दी थी जिसकी वजह से मिलें चल नहीं सकती थीं, उसके बाद धीरे-धीरे सूरत का डेवलेपमेंट होने लगा। वहां से मेरे भाई साहब बोल रहे थे कि अगर इसको पहले से किया होता तो बहुत अच्छा होता। मैं आप सब की जानकारी के लिए बता दूं, मेरे ख्याल से 1969 में National Taxtile Corporation शुरू हुआ और श्याम प्रसाद वसावडा उसके पहले चेयरमैन बने। उसके बाद से ज्यादा से ज्यादा टैक्सटाइल्स के यूनिट्स गुजरात के अंदर लगाए गए। उनमें से थोड़े बंद भी हुए और थोड़े चालू भी हुए। उसके बाद के दौर में दूसरी मिल्स भी बंद हुईं। जितना NTC का modernization होना चाहिए था उतना नहीं हुआ for many reasons. I don't know. मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता हूं। जितनी मिलें शहर के अंदर बनीं, जैसा कि अभी यहां पर बताया गया कि मिलों की जमीनें शहर के बीचों-बीच आई हैं और उन जमीनों की कीमत बहुत ऊंची है जिसकी वजह से हर एक को यह लालच होता है कि उसकी जमीन हमारे हाथ में आ जाए। हालांकि जो फार्स्ट जेनरेशन मिल मालिकों की थी, वह तो चली गई और जब सेकेंड और थर्ड जेनरेशन की तरफ से हाई कोर्ट में लिटिगेशन्स आईं, तो अब ये सब मिलें टूट रही हैं और यह सब जमीन खाली हो रही है। कितनी जगहों पर NTC ने मिलें ली हैं और उसके सामने लीज का सवाल खड़ा हुआ है, लेकिन मेरा यह मानना है कि सिर्फ लीज से ही प्रश्न हल नहीं हो सकेगा। सर, ओवरआल टैक्सटाइल सेक्टर को देखने की जरूरत है और इसके अंदर मैं modernization के अलावा कुछ और देखता नहीं हूं। यह इतना बड़ा सेक्टर है और इसके अंदर इतनी बड़ा एक्पलॉयमेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ मिलों में काम करने वालों की बात नहीं है, सर, मिल के अंदर नट-बोल्ट बनाने वाले, इतने कारखाने थे, वे सब कारखाने बंद हो गए हैं। जो उसका माल ले जाने वाले लॉरी वाले वे सब बेकार हो गए। जो कलर सप्लाई करने वाले थे, वे लोग भी बेकार हो गए। इसके इर्द-गिर्द जो पूरी इकोनामी घूमी हुई थी, वे सभी इसके विक्टिम्स बने। इसकी वजह से इस सेक्टर के अंदर जितना हमारा ध्यान होना चाहिए था, मैं इस बात को मानता हूं कि उतना ध्यान इस पर नहीं दिया गया। हालांकि लास्ट की यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने जितना हो सका, उतना करने का प्रयत्न किया।

सर, NTC की सबसे पहली शुरुआत उस वक्त में कांग्रेस की सरकार ने की थी और मेरे ख्याल से श्रीमती इंदिरा जी ने 1969 में इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद थोड़े साल यह अच्छी तरह से चली, लेकिन आज NTC को और भी स्ट्रैंथन करने की जरूरत है। हमारे पास में एक

अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट एवेलेबल है कि जब कोई प्राइवेट ओनर ज्यादा से ज्यादा केपिटल शिफ्ट करता है, एक इंडस्ट्री में से दूसरी इंडस्ट्री में वह डालता है, ले जाता है, तो जो मेन इंडस्ट्री होती है, वह सफर करती है और टेक्सटाइल इसका बेस्ट एक्जाम्पल है। उसमें से उन्होंने जितना भी पैसा कमाया, वह pough back नहीं किया, it was invested in some other industries. इसकी वजह से इतनी बड़ी paucity of funds हुई जिसकी वजह से जो बैंकों से पैसा लिया गया, वह नहीं दिया गया और इसकी वजह से मिलों का बंद होना शुरू हुआ। NTC की बड़ी मौके की जमीन है और इसके बारे में अभी शरद यादव जी बता रहे थे। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि इतनी बड़ी जमीन का कुछ परसेंटेज या तो सरकार ले सकती है और उसे लोगों के लिए रखना चाहिए। Artisan वगैरह को भी डेवलप करना चाहिए।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए।*)

मुझे उम्मीद है कि टेक्सटाइल मिनिस्टर ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। वैसे तो ये तेरहवीं लोक सभा और चौदहवीं लोक सभा के हमारे पुराने साथी रहे हैं, इसलिए मुझे उनको कहने का थोड़ा सा हक बनता है कि जब स्पेशली NTC का टेक्सटाइल यूनिट बंद पड़ा है, तो आप ऐसी नौबत ही मत आने दीजिए। मैं प्राइवेट के लिए मान सकता हूं, लेकिन जब NTC का यूनिट बंद पड़ा हो, तो आप ऐसी नौबत नहीं आने देंगे, क्योंकि यूनिट बंद होने के बाद उसमें काम करने वाले लोगों की फेमिली के साथ जो परेशानियां शुरू होती हैं, वे unbearable होती हैं। हालांकि Sir, I must say कि इस देश की economy इतनी resilient होने के बावजूद भी इस देश के अंदर इतनी सारी टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हुईं और हजारों मजदूर बेकार हुए, फिर भी कहीं न कहीं उसको absorb किया। किसी ने या तो सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया या रास्ते में कुछ और चीज बेचकर गुजारा किया। आज सूरत बहुत बड़ा सेन्टर हो गया है। यहां पर पहले 15-20 लोगों ने छोटी-छोटी फैक्ट्रियां शुरू की थीं। हालांकि सूरत में सबसे ज्यादा मजदूर ओडिशा से आए हैं और उनका सबसे ज्यादा exploitation होता है। अभी हमने जो कानून पास किया है, इसके अंदर 39 से कम मजदूर अगर काम करते होंगे, तो उनके लिए कोई रिकार्ड रखने की या बताने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ इन्स्पेक्टर को ही बताना होगा। अगर ऐसे 39 आदमी पावरलूम फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वे चाहे सालों तक काम करते रहें, लेकिन उनको permanent करने के लिए अगर कोई चीज करनी होगी, तो हमारे पास या यूनियन के पास कुछ नहीं होगा।

सर, इस देश में दो सबसे बड़ी मजदूर यूनियन्स हैं- एक तो मुम्बई की RMMS है और दूसरी गुजरात की टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है। इनके अंदर हजारों मजदूर यूनियन के मेम्बर थे और यूनियन्स सरकार से बिना पैसा लिए चलती थीं। यह एक classic example था कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट किस तरह चलाना चाहिए। वे दोनों ही यूनियन्स इसकी वजह से खत्म हो गईं। मैं मानता हूं कि सूरत की जो सिल्क मिल की इंडस्ट्री थी, वह भी बंद हो गई। मैं समझता हूं कि उसको भी इसमें maximum protection मिलना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि टेक्सटाइल यूनिट को बंद मत होने दीजिए। मैं चाहता हूं कि NTC तो बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए। अहमदाबाद में यह example है कि मॉडर्नाइज न करने की वजह से NTC की यूनिट भी बंद हो गई है। इस कारण से परिस्थिति और भी खराब हुई है। मैं कहता हूं कि आप ऐसी

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

परिस्थिति मत आने दीजिए। अगर उसको लीज देनी पड़े, तो लीज भी दे दीजिए, लेकिन मैनेजमेंट भी इतना ही दीजिए जिसकी वजह से यूनिट के अंदर जो pilferage होता है, खासकर कपड़ों की चोरी होती है, वह रुके। सब-स्टैंडर्ड माल दिया जाता है, प्रिंटिंग का माल सब-स्टैंडर्ड होता है। वैसे तो कॉटन सब-स्टैंडर्ड दिया जाता है। ये जो सब चीजें हैं, आप कैसे उसको टाइट करोगे, जिसकी वजह से NTC यूनिट्स में मैक्सिमम प्रॉफिट होफ मुझे प्रॉफिट में भी ज्यादा इंट्रस्ट नहीं है। प्रॉफिट है तो ठीक है, लेकिन मजदूरों की रोजी-रोटी चलती रहे और उनकी फैमिलीज को किसी प्रकार की यातना न मिले, क्योंकि हम भुगत चुके हैं। मेरा आग्रह है कि एक तरह की परिस्थिति पैदा न हो। मुझे पता नहीं है कि NTC के पास अपना रिजर्व फंड है या नहीं है, नहीं है तो उनको रिजर्व फंड रखना चाहिए। हाई कोर्ट में बैंकों के साथ NTC के केसेज चल रहे हैं, जिनमें लेबर को कर्जा पहले देने के बजाय उनका लास्ट में नम्बर आता है। इसलिए प्रोविडेंट फंड के पैसे जो मालिकों के पास बाकी हैं, अगर वे लैंड बेचते हैं, तो उसका सबसे पहला हिस्सा मजदूरों को दिया जाना चाहिए, ग्रेच्युटी के पैसे बाकी हों तो उनको वे दिए जाने चाहिए। पहले एक जमाने में लोग ज्यादा कपड़ा नहीं खरीदते थे और मजदूरों को ही खुद कपड़ा ले जाकर बेचना पड़ता था और उनको तनख्वाह भी कपड़े के रूप में ही दी जाती थी। वे कहते थे कि आप कपड़ा ले जाओ और खुद बेचो और उससे अपनी तनख्वाह लो। मेरे ख्याल से सबसे पहली मिल तो 1908 या 1909 में अहमदाबाद में शुरू हुई थी, उसके बाद ही दूसरी मिलें शुरू हुई हैं। वे पूरे देश के अंदर, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा इसी सिटी के अंदर थीं। जो "Payment of Wages Act" है, जिसके तहत आप कोई भी चीज़ goods के अंदर नहीं दे सकते, इसी तरह से "Industrial Relations Act" है। जिसके अंदर यदि recognised union के अलावा दूसरी यूनियन है तो वह इसके अंदर नहीं हो सकती है, जो "Industrial Disputes Act" है, इसके अन्दर कुछ भी हो, आप नोटिस दिए बिना लोगों को retrench नहीं कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये सब जो कानून हैं, यदि इन कानूनों में, खास कर के यदि 1992 के बाद कमी है, ज्यादा से ज्यादा casualty आई हुई है, तो वह labour department के अंदर आई है। NTC के अंदर काम करने वाले मजदूर को NTC Act, एक आदर्श employee of the ईयर का जो example है, वह उसको वहां पर पूरा example बनने दे। इस वजह से जहां-जहां पर जो मिलें बंद होती हैं, उन बंद मिलों के अंदर उनका जो सबसे पहला अधिकार हो, जैसे बकाया पैसा का है, वह मजदूरों के साथ हो। वह पैसा मजदूरों को सबसे पहले दिया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें करते हुए, see to it कि मिल बंद करने पहले यदि electric बिल न भरा हो, जिससे उसकी पूरी electric supply cut हो जाए, लोग बेकार हो जाएं, ऐसी परिस्थिति में आने से पहले ही उस unit को देखा जाना चाहिए और यदि उन मजदूरों का सवाल है, तो उसको हल करना चाहिए। यह तो सब स्वदेशी है, पहले तो हम स्वतंत्रता की लड़ाई में विदेशी माल की होली जलाते थे। जो विदेशों से कपड़ा आता है, उस कपड़े को ही सबसे ज्यादा जलाया जाता था, लेकिन आज तो इस देश का सवाल है, इसलिए सभी sectors एक साथ चलने चाहिए। अगर textile का बना हुआ कपड़ा अच्छी तरह का है तो उसमें जाना चाहिए, handloom से बने कपड़े और खादी का भी उतना ही अधिकार है। मैं यह मानता हूं कि टैक्सटाइल के अंदर जो खादी है, silk है, handloom है और अन्य units हैं, इस सभी को एक

साथ देखते हुए, उसमें maximum employment खड़ा हो और छोटे से छोटे शहर के अंदर भी ऐसी एक-एक, दो-दो छोटी यूनिट्स चलती हों। ऐसी जगह पर spinning की भी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं क्योंकि खादी में इतना बड़ा employment है। अभी वहां सामने से मेरे भाई बता रहे थे कि यदि यह export का है तो ज्यादा से ज्यादा हमारा है। मैं यह मानता हूं कि इस देश के अंदर लोगों के पास दो जोड़ी कपड़े से तीसरी जोड़ी कपड़े नहीं होते। यदि उनके पास तीन-चार जोड़ी कपड़े होते तो, वे अपने बैग के अंदर रखते, कि यदि पसंद आया, अच्छा लगा तो दीवाली, होली या किसी अन्य अवसर पर, नए कपड़े पहनेंगे, बाकी तो वे केवल दो जोड़ी से ही काम चलाते हैं। इस देश के अंदर चार-पांच जोड़ी कपड़े मिल जाएं, उसके बाद जिसको जितना एक्सपोर्ट करना हो, करे, लेकिन पहले देश की जरूरतें पूरी करेंगे, तो बहुत होगा। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आप इस देश के आदमी की जितनी purchasing power बढ़ाएंगे, उनकी उतनी ही हेल्प होगी। इस वजह से मेरी Textile Minister से विनती है कि आप NREGS को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दीजिए, जिससे rural areas के अंदर purchasing capacity जाए, उनके पास पैसे जाएं, उनकी purchasing power बढ़े, वे कपड़े खरीदें और textile units चलें। इससे silk यूनिट्स चलें, खादी यूनिट्स चलें, तेल भी बिके और गांव भी आबाद हों। आप उस लेवल तक जाइए। गांधी ने जो चरखा और तकली कही थी, उसका दूसरा स्वरूप NREGS ही है। हरेक हाथ को काम देना चाहिए और जब हरेक हाथ काम करता है तो उसको पैसे भी मिलें, जिससे इस देश की economy सबसे ज्यादा बढ़ेगी। Thank you very much, Sir, for allowing me to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Shri M.P. Achuthan.

SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala): Sir, this is a small Bill and its purpose is very simple. So, I support the Bill because we have to retain the land in the Government sector, the NTC. Now, we know that when the textile mills were nationalized, their aim was to retain the workers, that is, their job security. That was the main aim. But have we achieved it? We should see what the NTC has done and what the Government is doing now. According to the statistics released by the NTC, you have given VRS to nearly 70,000 workers. VRS means you are just giving some thousands of rupees and throwing out the workers. How have you mobilized the money? You have done it by selling the property, by selling the prime land in cities like Mumbai. You sell the land to the real estate businessmen, and throw away the workers. Can we forget the heroic textile workers of Mumbai? The textile workers of Mumbai had fought a heroic war in India's freedom movement. In 1908, when Bal Gangadhar Tilak was arrested and jailed for six years, and was deported to Burma, the textile workers of Mumbai were on strike for six continuous days. When the RIN Mutiny took place, the textile workers of Mumbai came out in solidarity and fought such a heroic war, such a patriotic war. Those workers have been thrown out of the job. I charge that there was a sinister move to wreck and demolish

[Shri M.P. Achuthan]

not only the trade union movement, but also the workers as a whole in Mumbai. So, my request to the hon. Minister is, when you take over the land, when you retain the land, when you sell the land, it must be for modernization. That was the declared aim of NTC and the Government. You had said that this amount would be for modernization. But did you do it? No. Did the Government do it? Did the NTC do it? No. Still the NTC mills are in red. Maybe, they are making some profit. But how many people have you employed? With that machinery, are you able to compete with the private sector in India and in the international market? There is a very big scope for the textile industry now. So, have a holistic view of it. In my State Kerala, we have got three mills. One is the Parvathi Mill in Kollam. This Mill had been closed down many years back. The machinery has been taken over partially. Now there is a move to revive it under PPP model. Those who are coming under PPP model, their aim is not to revive the mill and give them employment. You have got the prime land in the heart of the city. So, I request the Minister not to succumb to such a move of some real estate businessmen. The State Government has requested for some acres of land for building a medical college. If you are willing to give some land for medical college, then the other portion can be utilized for the revival of the mill. In Pondicherry, there are some textile mills, and one is in Mahe near Kerala. They have requested for ₹ 500 crore relief package for the revival of the textile mills in Pondicherry. Please do it. My request is, take a holistic view not only of the textile mills, NTC mills, but also of the cotton growers, handloom workers, handloom industry and textile industry. Without taking a holistic view, we cannot solve the problem of the textile sector. If we see where the farmers' suicides are taking place, most of them are taking place in the cotton growing areas. So, if you want to save the farmers and ensure the remunerative price to the farmers, you must have a wide range textile industry and a handloom sector. Handloom is one of the best traditional industries of our country. We have to revive it, we have to sustain it. Therefore, I request the Minister to take a holistic and comprehensive view and make a comprehensive programme for the revival of the textile sector and the handloom industry of our country. Thank you.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Repealing and Amending Bill, 2014

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-